



ब्रीफ न्यूज

तीन विज्ञानियों को मिलेगा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज

संवादाता

नई दिल्ली (एजेंसी) : सुसुमु कितानावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. याची को रसायन विज्ञान में अभूतपूर्व कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये वैज्ञानिक दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और तीनों में सबसे छोटे उमर एम याची ने तो बचपन जॉर्डन के रिफ्यूजी कैम्प में बिताया है। चारों ओर इन तीन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की चर्चा है, क्योंकि ये आम जिंदगियों से जुड़ी हैं।

सिंगर जुबीन गर्ग

मौत केस में चचेरा भाई गिरफ्तार

गुवाहाटी (एजेंसी) : सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में बुधवार को असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया गया है। संदीपन, सिंगर के चचेरे भाई हैं। हादसे के वक्त वह सिंगापुर में साथ थे। अधिकारी ने बताया कि संदीपन से जुबीन की मौत के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ में 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण



एजेंसी

छत्तीसगढ़ : बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सल प्रभावित माड़ डिवीजन के 70 लाख रुपये के इनामी सखित कुल 16 नक्सलियों ने नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुडिया के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित 16 नक्सलियों में 9 पुरुष और 7 महिला नक्सली शामिल हैं। समर्पण करने वालों में एक डिप्टी कमांडर स्तर का नक्सली भी है, जो कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। नारायणपुर एसपी रॉबिंसन गुडिया ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सली लंबे समय से अलग-अलग नक्सली दलों से जुड़े थे और नारायणपुर, अबुलमाड़, ओरछा, व बस्तर क्षेत्र में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों में शामिल डिप्टी कमांडर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सुरक्षाबलों पर हमला, आईईडी विस्फोट और ग्रामीणों की हत्या जैसे संगीन अपराध शामिल हैं।

न्यूजस्टडी

होमटाउन की ही केंद्रीय कारा में बंद है रेड्मा का रहने वाला गैंगस्टर, गैंगवार की आशंका

पलामू जेल में है सुजीत सिन्हा, सुपरिटेण्डेंट की सिफारिश के बाद भी नहीं हुआ शिफ्ट

एजेंसी

रांची: अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कोयलांचल में घौस जामने के लिए कई अपराधी लाइन लगाए हुए हैं। इनमें एक नाम सुजीत सिन्हा का भी है। झारखंड का कुख्यात सुजीत सिन्हा पलामू सेंट्रल जेल में बंद है। सुजीत सिन्हा पलामू के रेड्मा का रहने वाला है। अपने ही जिले का कुख्यात आज वहाँ की जेल में कैद है, जहाँ कभी उसके खौफ की कहानियाँ सुनाई देती थीं। होमटाउन की जेल में रहने से उसे किसी भी तरह की सुविधा की कोई दिक्कत नहीं होती है। इस कारण जेल में गैंगवार का भी खतरा बढ़ा हुआ है। जेल सुपरिटेण्डेंट भागीरथी कारजी के अनुसार, सुजीत को पलामू जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट कराने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में उन्होंने बताया है



कि पलामू जेल में स्थानीय अपराधी भी बंद हैं। ऐसे में सुजीत सिन्हा का पलामू जेल में रहना खतरनाक हो सकता है। जेल सुपरिटेण्डेंट ने गैंगवार की आशंका भी जाहिर की है। फोटोन संवाददाता से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि होमटाउन के जेल में रहने के कारण गैंगवार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि, सुजीत सिन्हा के इस जिले में कई विरोधी हैं। जेल

सुपरिटेण्डेंट के पत्र लिखने के बावजूद सुजीत सिन्हा को अब तक पलामू सेंट्रल जेल में ही रखा गया है। इसके फेसबुक आईडी को देखने से साफ पता चलता है कि अपराधी का नेटवर्क भी इसी से ऑपरेट किया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम हत्या, वसूली, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामलों से जुड़ा है। सुजीत सिन्हा पर राज्यभर में दर्जनों केस दर्ज हैं।

जेल से भी कॉरपोरेट स्टाइल में गैंग चला रहा है कुख्यात

बावजूद सुजीत सिन्हा का सोशल मीडिया अकाउंट लगातार एक्टिव है। उसके फेसबुक आईडी को देखने से साफ पता चलता है कि अपराधी का नेटवर्क भी इसी से ऑपरेट किया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम हत्या, वसूली, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामलों से जुड़ा है। सुजीत सिन्हा का नेटवर्क भी इसी से ऑपरेट किया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम हत्या, वसूली, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामलों से जुड़ा है। सुजीत सिन्हा पर राज्यभर में दर्जनों केस दर्ज हैं।



सके। नई दिल्ली में बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एफिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लांच किया जिसका

प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष पेश किया गया। आप एटीएम पर बायोमेट्रिक लगाएँ और वह आपके थैले में राशन का अनाज उगल देगा। ऐसे एटीएम से एक बार में 25-30 किलोग्राम राशन लिया जा सकता है। अब देशभर में जल्द ही 'राशन एटीएम' आम जनता के लिए सुविधा का नया माध्यम बन सकते हैं। इस तकनीक के जरिए कोई भी लाभुक अपने आधार आधारित बायोमेट्रिक

वेरिफिकेशन से सीधे मशीन से राशन प्राप्त कर सकेंगे। मशीन कार्डधारक के खाते में दर्ज कोटे के अनुसार तय वजन में अनाज देगी। यदि कोई लाभुक एक बार में पूरा कोटा नहीं लेना चाहता, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार शेष राशन बाद में निकाल सकता है। इस प्रयोग का 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को प्रभावी तरीके से उतारने की दिशा में पहलके रूप में देखा जा रहा है,

डब्ल्यूआईआई के भेजे गए जवाब और मैप का उल्लेख



सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के मुकाबले क्षेत्रफल में वृद्धि का कारण जानना चाहा। राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए डब्ल्यूआईआई द्वारा भेजे गए जवाब और मैप का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूआईआई ने अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए पहले आठ साल का समय मांगा और इस पर तीन करोड़ रुपये का खर्च बताया। इसके बाद डब्ल्यूआईआई ने एक मैप भेजा, जिसमें 55,19.41 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल डीएफओ के स्तर से होते हुए पीसीसीएफ तक पहुँची। इस पर सरकार की सहमति नहीं थी। वन सचिव ने इसी प्रस्ताव की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दी थी। सरकार को एनजीटी के दिशा निर्देश के आलोक में 31,468.25 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए न्यायालय सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने की अनुमति दे।

हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट में दी यह दलील

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एनजीटी ने सारंडा जंगल के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया था, जिसपर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बाद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित अभयारण्य का क्षेत्रफल बढ़ाकर 57,519.41 हेक्टेयर कर दिया। इससे कई खनन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि इतने बड़े क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया, तो वहाँ दशकों से चल रही लौह अयस्क और अन्य खनिजों की खदानों पर रोक लग जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वर्षों से जो खनन कार्य कानूनी रूप से चल रहे हैं, उन्हें बंद करने से देश-राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा।

सारंडा वन क्षेत्र मामले पर झारखंड सरकार को मिली 'सुप्रीम' राहत

57,519.41 नहीं, सिर्फ 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र घोषित होगा अभयारण्य

एजेंसी

रांची/ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को ही अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को 8 अक्टूबर 2025 तक अभयारण्य घोषित करने का आदेश था। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), एमिक्स क्यूरी और अन्य संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने सेल और वैध माइनिंग लीज वाले क्षेत्रों को अभयारण्य की सीमा से बाहर रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड सरकार को मांग स्वीकार कर ली और 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया था,

हेमंत सरकार को 'सुप्रीम' राहत, सेल और वैध माइनिंग लीज को इस एरिया के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का मिला आदेश

डब्ल्यूआईआई के भेजे गए जवाब और मैप का उल्लेख



सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के मुकाबले क्षेत्रफल में वृद्धि का कारण जानना चाहा। राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए डब्ल्यूआईआई द्वारा भेजे गए जवाब और मैप का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूआईआई ने अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए पहले आठ साल का समय मांगा और इस पर तीन करोड़ रुपये का खर्च बताया। इसके बाद डब्ल्यूआईआई ने एक मैप भेजा, जिसमें 55,19.41 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव से संबंधित फाइल डीएफओ के स्तर से होते हुए पीसीसीएफ तक पहुँची। इस पर सरकार की सहमति नहीं थी। वन सचिव ने इसी प्रस्ताव की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दी थी। सरकार को एनजीटी के दिशा निर्देश के आलोक में 31,468.25 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए न्यायालय सरकार को 31,468.25 हेक्टेयर को सैंडूचि घोषित करने की अनुमति दे।

हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट में दी यह दलील

सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एनजीटी ने सारंडा जंगल के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया था, जिसपर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बाद में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित अभयारण्य का क्षेत्रफल बढ़ाकर 57,519.41 हेक्टेयर कर दिया। इससे कई खनन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि इतने बड़े क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया, तो वहाँ दशकों से चल रही लौह अयस्क और अन्य खनिजों की खदानों पर रोक लग जाएगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वर्षों से जो खनन कार्य कानूनी रूप से चल रहे हैं, उन्हें बंद करने से देश-राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा।

लो आ गई मशीन, इधर अंगूठा लगाओ, उधर से निकलेगा गेहूँ-चावल

एजेंसी

नई दिल्ली : आप राशन कार्डधारक हैं। आपको अपने कोटे का राशन लेना है तो आपको डीलर के वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन, आने वाले दिनों में शायद आपको इसकी जरूरत न पड़े। जैसे अब पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह देश में ऐसे एटीएम लगाए जाने का विचार है, जहाँ से आप अपने कोटे का राशन खुद ले



सके। नई दिल्ली में बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एफिक्सन कंपनी ने राशन एटीएम लांच किया जिसका

वेरिफिकेशन से सीधे मशीन से राशन प्राप्त कर सकेंगे। मशीन कार्डधारक के खाते में दर्ज कोटे के अनुसार तय वजन में अनाज देगी। यदि कोई लाभुक एक बार में पूरा कोटा नहीं लेना चाहता, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार शेष राशन बाद में निकाल सकता है। इस प्रयोग का 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना को प्रभावी तरीके से उतारने की दिशा में पहलके रूप में देखा जा रहा है,

बिहार विस चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में झारखंड पुलिस

एजेंसी

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। बॉर्डर वाले जिलों में मादक पदार्थों और अवैध हथियार, पैसे और शराब की तस्करी पर ब्रेक लगाने के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से झारखंड के सभी जिलों के एसएम्पी व एसपी को अलर्ट जारी किया गया है। आईजी अभियान ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भी भेजा गया है। झारखंड के



पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिया गया है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता-सहआईजी अभियान डॉ.

माइकल राज ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर अवैध शराब और मादक पदार्थों के निर्माण, व्यापार, परिवहन और तस्करी के रोकथाम के लिए सभी तरह के निरोधक कार्रवाई करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी अभियान ने बताया कि पूर्व में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएस और डीजीपी के स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं।

मांडर में राजकीय मुड़मा जतरा शुरू, मंत्री शिल्पी नेहा तिकी हुई शामिल

संवाददाता

रांची : राजकीय मुड़मा जतरा का दो दिवसीय आयोजन शक्ति खंडा स्थल पर विधिपूर्वक पूजा-अर्चना एवं जल अर्पित कर शुरू हुआ। देशभर से हजारों लोग इस ऐतिहासिक जतरा में शामिल हुए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने जतरा को संबोधित करते हुए कहा कि वह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहाँ थोड़ी दूरी पर रहन-सहन, खान-पान और बोली बदल जाती है। उन्होंने बताया कि रोहतासगढ़ से उर्वा समाज के लोग जब यहाँ पहुँचे तो मुंडा समाज ने उन्हें बसाने का काम किया। मुड़मा स्थल मुंडा और उर्वा समाज के मिलन और समागम के लिए जाना जाता है। शिल्पी नेहा तिकी ने कहा कि यह जतरा साधारण नहीं है, बल्कि पुरखों की



पहचान, सामूहिकता, एकता और भाईचारे की विश्वास को बनाए रखने का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि

राजकीय मुड़मा जतरा के प्रति आस्था और ख्याति हमेशा बनी रहे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास जारी रहेंगे।

आरयू में वन नेशन वन इलेक्शन पर राष्ट्रीय परिचर्चा, नेता प्रतिपक्ष बोले- एक साथ चुनाव से देश को मिलेगी नई दिशा

रांची, संवाददाता ।

रांची विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज सेंटर सभागार में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के तत्वावधान में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कई शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ और विभिन्न विषयों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए।

वक्ताओं ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' की अवधारणा पर डली रोशनी

कार्यक्रम की शुरुआत में वक्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है भारत में लोकसभा, विधानसभा



और स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ कराना ताकि बार-बार चुनाव से होने वाले समय, धन और प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सके। वक्ताओं ने बताया कि 1952 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे लेकिन बाद में राज्यों में सरकारें समय से पहले गिरने के कारण यह क्रम टूट गया। अब केंद्र सरकार इसे

देबारा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2024 में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दी और संसद में इसे प्रस्तुत

किया।

बार बार चुनाव होने से लागू होता रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट

परिचर्चा में उपस्थित शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने भी इस प्रस्ताव के फायदे और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि बार-बार चुनाव होने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता रहता है, जिससे विकास कार्य रूक जाते हैं। वहीं एक साथ चुनाव से सरकारी खर्च में कमी आएगी, प्रचार अभियान सीमित होंगे और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।

एक साथ चुनाव करने से राष्ट्रीय जीडीपी गीथ में 1.5% तक की वृद्धि का अनुमान

सांख्यिकीय रूप से बताया गया है कि देश में एक साथ चुनाव लागू

किए जाए तो 2029 में इसकी अनुमानित लागत लगभग 7,951 करोड़ रुपये होगी जबकि अलग-अलग चुनाव कराने पर इससे कई गुना अधिक खर्च होता है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने और राष्ट्रीय जीडीपी गीथ में 1.5% तक की वृद्धि का अनुमान भी जताया गया है।

'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रशासनिक पारदर्शिता में ऐतिहासिक कदम

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी इस विषय पर सवाल पूछे और अपने सुझाव साझा किए। आखिर में वक्ताओं ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

आईएस विनय चौबे ने विनय सिंह की मौजूदगी में सीओ अलका कुमारी को ऑफिस बुलाकर कराया था म्यूटेशन

72 डिसिमिल भूमि रैतीली खाते की थी और 28 डिसिमिल भूमि नरकजरा आखास क्रिसम की भूमि का हुआ था म्यूटेशन।

म्यूटेशन को विनयचिच्छु बताने पर विनय चौबे ने राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को बुलाया और जांच रिपोर्ट देके का आदेश दे दिया।

राजस्व कर्मचारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीसी विनय चौबे को कहने पर किया म्यूटेशन।

रांची, संवाददाता ।

हजारीबाग वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी ने 7 अक्टूबर को एडीएम रैंक की अफसर अलका कुमारी का बयान हजारीबाग अड्ड की विशेष कोर्ट में दर्ज करवाया है। अलका कुमारी पूर्व में हजारीबाग जिले में सदर सीओ के पद पर पदस्थापित रह चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि वर्ष 2010 में जब वह हजारीबाग जिले में सदर सीओ के पद पर पदस्थापित थीं उस दौरान एक दिन तत्कालीन उड विनय चौबे ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। जब वह डीसी



के कार्यालय पहुंची तो वहां एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था। विनय चौबे ने उस व्यक्ति का परिचय कराते हुए बताया कि उस व्यक्ति का नाम विनय सिंह है। जिसके बाद अलका कुमारी को एक दस्तावेज दिया गया और दाखिल खारिज (म्यूटेशन) करने की बात कही गई। दस्तावेज का निरीक्षण करने पर पता चला कि 72 डिसिमिल भूमि रैतीली खाते की थी और 28 डिसिमिल भूमि गैरमजरूआ खास क्रिसम की भूमि थी।

अलका कुमारी ने विनय चौबे को यह बताया कि गैरमजरूआ खास क्रिसम की भूमि का म्यूटेशन करना नियमसंगत नहीं है। इसके बाद विनय चौबे ने राजस्व

कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को बुलाया और जांच रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया। विनय चौबे के आदेश के बाद राजस्व कर्मचारी और सीआई ने कुछ ही समय में अपनी रिपोर्ट दे दी। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीसी विनय चौबे ने कहा कि रिपोर्ट आ गई अब म्यूटेशन करी। विनय चौबे द्वारा म्यूटेशन के लिए कहने पर जब अलका कुमारी ने विरोध किया तो उन्हें विनय चौबे ने कहा कि यह एक आदेश है जिसका अनुपालन करना है। जिसके बाद उनके आदेशानुसार औपचारिकता निभाते हुए विनय सिंह और उनकी पत्नी सिन्धा सिंह के नाम से उक्त भूमि का म्यूटेशन किया गया।

टीसीएस में जाँब पाने का सुनहरा अवसर, मारवाड़ी कॉलेज में टीसीएस प्री-प्लेसमेंट टॉक



रांची, संवाददाता ।

मारवाड़ी कॉलेज, रांची के प्लेसमेंट सेल द्वारा आज आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से प्री-प्लेसमेंट टॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के बीए, बीकॉम और बीबीए विभागों के 2024, 2025 और 2026 में स्नातक होने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान टीसीएस की टेक्निकल टीम ने विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए तथा कंपनी में आवेदन की प्रक्रिया और चयन

परीक्षा की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। जानकारी दी गयी कि टीसीएस की भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2025 को टीसीएस आयन डिजिटल सेंटर में आयोजित की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से 19 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भर सकते हैं। मारवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर तक किये जा सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ऊपर से चौबे लिंक पर क्लिक कर विद्यार्थी एनरोल कर सकते हैं।

बिहार चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश

रांची, संवाददाता ।

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अभियान डॉ. माइकल राज ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है। बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए



झारखंड पुलिस की ओर से विशेष तैयारी की गयी है।

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान डॉ. माइकल राज ने बुधवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर अवैध शराब और मादक पदार्थों के निर्माण, व्यापार, परिवहन और तस्करी को रोकथाम के लिए सभी तरह के निरोधात्मक कार्रवाई करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। आईजी अभियान ने बताया कि चुनाव आयोग के जरिए जो भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार तमाम तरह की सतर्कता झारखंड पुलिस की ओर से बरती जा रही है। अवैध नकदी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जितना नकद ले जाने की

इजाजत आम लोगों को मिलती है। अगर उससे ज्यादा कोई नकद लेकर जाता है, तो उस पर नजर रखने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में चेक पोस्ट भी तैयार किया जा रहे हैं। सभी चेक पोस्ट पर बिहार पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। आईजी ने बताया कि वैसे झारखंड के जिले, जो बिहार से सटे हुए हैं, वहां के पुलिस अधीक्षक अपने बिहार के निरक्षेत्री जिलों के पुलिस अधीक्षकों से समन्वय स्थापित कर अंतर जिला बैठक करेंगे। इसके अलावा अंतर राजकीय बैठक की भी रणनीति तैयार की गई है। झारखंड पुलिस की तरफ से प्रदेश के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है।

गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट झारखंड के पर्यावरण के लिए घातक, भाकपा माले ने नीलामी रद्द कराने की मांग की

रांची, संवाददाता ।

भाकपा (माले) ने हजारीबाग में प्रस्तावित अडाणी गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट को राज्य के पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन के लिए घातक करार देते हुए इस परियोजना को तुरंत रद्द कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह परियोजना कॉरपोरेट स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान झारखंड की प्राकृतिक संपदा और आदिवासी ग्रामीणों को झेलना पड़ेगा। भाकपा माले राज्य कमिटी के नेता मनोज भक्त ने बयान जारी कर कहा कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित 1060 एकड़ अधिग्रहण क्षेत्र में से लगभग आधी जमीन वनभूमि है, जिसमें कई नदियां और जलस्रोत भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में कोयला खनन शुरू हुआ तो उत्तरी छोटानागपुर का पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और झारखंड की



पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। यह परियोजना अडाणी समूह के कॉरपोरेट हितों को साधने के लिए बनाई गई है। इसके चलते झारखंड को पर्यावरणीय विनाश और विस्थापन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

गांवों के 2000 परिवार होंगे विस्थापित

मनोज भक्त ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के हाड़े, फूलगं, बालोदर, गाली और गोंदलपुरा गांवों के लगभग 2000 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि जबरन भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार और

कंपनी द्वारा वन कानूनों, ग्रामसभा के अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों पर दबाव बनाने के लिए दलालों और बाहरी तत्वों का सहारा लिया जा रहा है। माले ने मांग की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोंदलपुरा कोल ब्लॉक की नीलामी को रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं और राज्य की जनता के प्रति अपनी स्पष्ट पक्षधरता दिखाएं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार चुप रही तो भाकपा माले आंदोलनरत ग्रामीणों के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर सख्त हुए अपर मुख्य सचिव, कंपनी को सुधार के निर्देश

रांची, संवाददाता ।

राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की लेटलतीफी और मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सख्त हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने एक आपात बैठक बुलाकर सेवा प्रदाता संस्था सम्मान फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाई और सेवा में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समाचार पत्रों में लगातार एम्बुलेंस के विलंब से पहुंचने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मरीजों को कष्ट हो रहा है, बल्कि राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति के एमडी शशि प्रकाश झा, कॉरपोरेशन के एमडी अबु इमरान तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य



सचिव ने स्पष्ट कहा कि एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता किसी भी सूरत में उत्कृष्ट होनी चाहिए और मरीजों को समय पर सेवा मिलनी चाहिए। उन्होंने एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लापरवाही या देरी की शिकायतें फिर से मिलीं, तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, 108 एम्बुलेंस सेवा की निगरानी कर रहे डॉक्टर पंकज को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 10 एम्बुलेंस की लाइव मॉनिटरिंग करें और वाहनों की स्थिति की नियमित रिपोर्ट विभाग को भेजें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा जनता की जीवनरेखा है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ते फोकस के साथ झारखंड में जागरूकता अभियान की शुरुआत

रांची, संवाददाता ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का शुभारंभ आज आईपीएच ऑर्टोडॉन्ट्रियम, नामकुम में हुआ। यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज की भागदौड़ पूरी जिंदगी में लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। नकारात्मक सोच और तनाव लोगों के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो उनके आस-पास का माहौल भी सकारात्मक बनेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अगर अपने खर्च का हिसाब लगाए तो वह उस पैसे से एक घर बना सकता है। श्री झा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है।



नियुक्ति की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉ सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि आज समाज में लोगों का आपसी जुड़ाव कम हो रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य बीमारियां जैसे टीबी और मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा रहा है, लेकिन मानसिक बीमारियों में वृद्धि हो रही है।

अब मेडिकल, मेंटल और सोशल वेलनेस पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में डॉ अश्विनी कुमार ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहा है। डॉ प्रीथा राय, लंगमग 120 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कहा कि कार्यस्थल पर ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जिससे तनाव और बर्नआउट से बचा जा सके। मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट शांताना ने बताया कि दुनिया की लगभग 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रसित है। लोगों के बीच संवाद की कमी और अकेलेपन की प्रवृत्ति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी, डॉ मधुमिता, डॉ पी के सिंह, डॉ लाल मांझी, नोडल अधिकारी डॉ पांडेय, डॉ पंकज, डॉ रणजित सहित विभिन्न सेल के कंसल्टेंट, जिलों एवं प्रखंडों के कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लिया।

कुड़मियों को एसटी दर्जा देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंटी झारखंड कांग्रेस!

रांची, संवाददाता ।

कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर, झारखंड कांग्रेस के अंदर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। राज्य के दो मुख्य समुदाय कुड़मी और आदिवासियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है, जबकि झारखंड कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे में पार्टी नेता दो राय में बंटते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ईटीवी भारत को दिए एकसक्लूसिव इंटरव्यू में छोटानागपुर के कुड़मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को काफ़ी पुराना बताया था। केशव महतो कमलेश ने कहा था कि सांसद के रूप में शिवु सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था। इस बयान के बाद अब कांग्रेस के



जनजाति समुदाय के नेता भी खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। आदिवासी बन जाने से कुड़मी समुदाय का नहीं हो जाएगा समाधान

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व कार्यालय प्रभारी अमूल्य नीरज खलखो ने कहा कि पूरे देश में कुड़मी, पिछड़े

वर्ग में शामिल हैं और उन्हें नहीं लगता कि उनके आदिवासी बन जाने से कुड़मी समुदाय की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की कही बातों से उलट यहां तक कह दिया कि आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र की

सरकार ने जो उत्तर दिया है, उससे साफ है कि 1931 में कुड़मी समुदाय की स्थिति क्या थी? इसकी कोई जानकारी नहीं है।

बैठक में पार्टी का स्टैंड होगा फ़ाइनल

पूर्व मंत्री एवं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिकी ने कहा कि यह काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और पीएससी यानी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ही कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का फैसला होगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद भी कुड़मी समुदाय से आते हैं, उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा था कि कुड़मी समुदाय द्वारा एसटी में शामिल करने की मांग बहुत पुरानी है, यहां तक कि अंग्रेज अफसर हर्बर्ट होप रिस्ले ने 10 कास्ट एंड ट्राइब्स की जो सूची जारी की थी

उसमें उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, संथाल के साथ कुड़मी को भी एसटी सूची में रखा था। उन्होंने यह भी कहा था कि दिशोम गुरु शिवु सोरेन ने भी सांसद रहते हुए कुड़मियों को एसटी में शामिल करने के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था।

झारखंड कांग्रेस के आदिवासी नेता भी हुए मुखर

केशव महतो कमलेश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में यह भी कहा था कि 1901, 1911, 1921 की जनगणना में कुड़मी को ट्राइब्स में रखा गया था। उन्होंने कुड़मी को एसटी में शामिल कर ओबीसी की तरह ST को भी दो अनुसूची ST-1 और ST-3 बनाने की बात भी कही थी। जिसके बाद से झारखंड कांग्रेस के आदिवासी नेता भी इस मुद्दे पर मुखर होने लगे हैं।

SAMARPAN LIVE
Samarpan Livelihood
LIFE CHARITY SUPPORT
"Always give without remembering and always receive without forgetting."
"An Attempt Towards Creation Of New Rays Of Life."

राजी पड़हा मुड़मा जतरा में आदिवासी संस्कृति की छटा उरांव और मुंडा समाज के मिलन स्थल 'शक्ति खूंटा स्थल' पर दो दिवसीय उत्सव शुरू

संवाददाता । रांची
रांची : रांची जिले के मांडर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक शक्ति खूंटा स्थल पर बुधवार से दो दिवसीय राजी पड़हा मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत हुई। पारंपरिक रीतिरिवाजों के साथ पूजा-अर्चना और जल अर्पण के बाद देशभर से पहुंचे लोगों ने जतरा में भाग लिया। पूरे परिसर में आदिवासी परंपरा, लोकगीतों और नृत्य की गुंज से वातावरण उत्सवमय हो उठा। इस मौके पर झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिरकी ने कहा कि यह जतरा सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हम अपने पुरखों की परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा है- जहां कुछ ही दूरी पर बोली, पहनावा, खानपान और रहन-सहन बदल जाता है। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत



रांची : मंत्री तिरकी ने कहा कि मुड़मा ऐतिहासिक मिलन का प्रतीक है। स्थल उरांव और मुंडा समाज के उन्होंने बताया कि 'जब उरांव समाज



के लोग रोहतासगढ़ से यहां पहुंचे, तब मुंडा समाज ने उन्हें यहांवासाया। यही से दोनों समुदायों के बीच भाईचारे और एकता की मिसाल कायम हुई। यह

जतरा हमारे सामूहिक विश्वास, पहचान और एकजुटता का प्रतीक है।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पारंपरिक जतरा की आस्था, ख्याति और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहें। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शक्ति खूंटा स्थल पहुंचे और उन्होंने पूजा- अर्चना कर मरांग बुरु से राज्यवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 'मुड़मा जतरा मेला आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो सामाजिक एकता और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाता है।' दो दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक जतरा में दूर-दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जगह-जगह पारंपरिक नृत्य, हाट- बाजार और स्थानीय व्यंजनों के साथ मेला का माहौल पूरे मांडर क्षेत्र में उल्लास और श्रद्धा से सराबोर हो उठा है।

ब्रीफ न्यूज



संवाददाता । रांची

रांची : रांची । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक, पद्म भूषण स्व. श्री राम विलास पासवान जी की पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिजेश प्रधान जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण तथा गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों की स्मरण किया। कार्यक्रम के उपरांत सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हार्दिक मूक बधिर विद्यालय (तपोवन मंदिर के समीप, निवारनपुर) पहुंचे, जहाँ विशेष बच्चों को प्रोत्साहन एवं सम्मान दिया गया। इस अवसर पर उन्हें स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के जीवन, उनके मानवतावादी दृष्टिकोण और समाजहित में किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर यह भी निर्णय लिया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को हार्दिक 1, बिहारी 1 र 2 के जन-आंदोलनात्मक नेटवर्क के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। साथ ही, पार्टी ने यह भी घोषणा की कि झारखंड प्रदेश इकाई घाटशिला उपचुनाव में एन.टी.ए. (उज्ज्व) के प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन देगी और गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश से आए पार्टी पदाधिकारी आदित्य विजय प्रधान, पासनाथ राय, अभिषेक राय, उमेश निवार, ममता रंजन, हाफिजुल हसन, रतन पासवान, शिव जी, उत्तम राय, दिनेश सोनी, मनीषा देवी, संतोष पासवान, आनंद वर्मा, विजय कुं, आनंद पांडे, सुरेंद्र राय, राजेश रंजन वर्मा, संजीत द्विवेदी, विकास राय, हरेश्वर जी, प्रतिज्ञा कुमार, तनिक, संदीप, भोला, मनीष, विजय, एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पांचवीं में बोर्ड परीक्षा बच्चों में झप आउट बढ़ायेगा - माकपा

संवाददाता । रांची

रांची : जैक द्वारा 5 वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लिए जाने के प्रस्ताव से शिक्षा के अधिकार कानून के केवल उल्लंघन ही नहीं होगा बल्कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बच्चों का स्कूल से पलायन भी बढ़ेगा। इतनी कम उम्र में बच्चों पर बोर्ड परीक्षा थोपने से उन पर मानसिक दबाव बढ़ेगा, यह प्रस्ताव शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 की पूरी तरह अवहेलना है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी छात्र को वर्ग आठ तक फेरल नहीं किया जा सकता है, इसलिए झारखंड सरकार का यह प्रस्ताव शिक्षा को केवल परीक्षा के दौरे बना देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्ग के छात्रों की परेशानी बढ़ाएगा। माकपा बच्चों की परीक्षा लिए जाने की विरोधी नहीं है लेकिन पांचवीं से ही बोर्ड परीक्षा तर्कसंगत नहीं है। परीक्षा समिति द्वारा यह प्रयोग सातवीं कक्षा के लिए पूर्व में भी किया गया था लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आए इसलिए सातवीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा लिए जाने का निर्णय वापस लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान

संवाददाता । रांची

रांची : यह घृणित हरकत देश के संवैधानिक मंदिर पर खुला प्रहार है ! यह मनुवादी विचारधारा का वह काला जहर है, जो सदियों से आदिवासी, दलित और वंचित समुदायों को संवैधानिक समानता से वंचित करने की नापाक साजिश रचता रहा है। विजय शंकर नायक उपरोक्त बातें आज आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केन्द्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय शंकर नायक ने मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई का अपमान जुता फेक कर करने पर अपनी प्रतिक्रिया में उक्त बातें कही इन्होंने आगे कहा की न्यायपालिका पर निंदनीय हमला मनुवादी गुंडे की जुलैबाजी हिंदुस्तान के संवैधानिक गौरव पर जहर है ! भारत के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, जो दलित समुदाय का अटूट अभिमान और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक शेर हैं, पर एक नीच, मनुवादी दुष्ट द्वारा जुता फेकने की घृणित हरकत देश के संवैधानिक मंदिर पर खुला प्रहार है ! यह वाचन्य, शर्मनाक और राष्ट्रविरोधी कुकृत्य हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के हृदय में संवैधानिक आग भड़काने वाला अपराध है ! हम, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, इस नरक से उभर कर संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए तीव्रता निंदित करते हैं और इसे हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर जहरीला दाग घोषित करते हैं ! यह जुता नहीं, मनुवादी विचारधारा का वह काला जहर है ! जो सदियों से आदिवासी, दलित और वंचित समुदायों को संवैधानिक समानता से वंचित करने की नापाक साजिश रचता रहा है ! मुख्य न्यायाधीश गवई जी, जिन्होंने खजुराहो मंदिर की विष्णु मूर्ति याचिका पर संवैधानिक निष्पक्षता का परचम लहराया, उन्हें धार्मिक भावनाओं का अपमान ठहराकर निशाना बनाना-यह मनुवादी अपराधियों की खुली संवैधानिक अवमानना है ! श्री नायक ने आगे कहा कि हिंदुस्तान का अटल संविधान और उसकी न्याय व्यवस्था इन दुष्टों को कानून की ताकत से चूर-चूर कर देगी ! हमारा देश, जो बाबासाहेब अंबेडकर, गांधी और फुले की संवैधानिक विरासत पर अडिग है, इन जहरीले तत्वों के सामने कभी सिर नहीं झुकाएगा ! हम उन सभी राष्ट्रविरोधी, मनुवादी और सांप्रदायिक षड्यंत्रकारियों को संवैधानिक कठोरता के साथ चेतावनी देते हैं- चाहे वे देश के भीतर के गद्दार हों या विदेशी साजिशों के कठपुतली-हिंदुस्तान की न्यायपालिका और संप्रभुता पर तनिक भी आंच डालने की हिमाकत न करें ! ये नीच ताकतें, जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से समाज को खंडित करने का दुस्साहस करती हैं, हमारे एकजुट संवैधानिक बल के सामने राख में मिल जाएंगी ! हम सरकार, पुलिस और न्यायिक संस्थाओं से संवैधानिक दृढ़ता के साथ मांग करते हैं कि इस घृणित अपराध की तत्काल और पारदर्शी जांच हो, इस मनुवादी अपराधी को कानून की कठोरताम सजा दी जाए, और मुख्य न्यायाधीशों की सुरक्षा को संवैधानिक कवच बनाया जाए ! आदिवासी मूलवासी समाज इन मनुवादी दुष्टों को संवैधानिक शक्ति से कुचल देगा और न्याय की ज्योति को अनंत काल तक प्रज्वलित रखेगा ! जय दलित आदिवासी ! जय हिंदुस्तान ! जय संविधान !

बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद के मुद्दे पर बैठक



संवाददाता । रांची

रांची । बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद से जुड़ी समस्या के समाधान में विलंब होने से हो रही कठिनाई पर आज चैंबर भवन में रांची नगर निगम किरायेदार संघ के पदाधिकारियों ने झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिलकर, मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। यह बताया कि वर्षों पूर्व जब निगम का अस्तित्व भी नहीं था, तब व्यापारियों को बाजार टांड में बसाया गया था। तत्कालीन समय में निगम द्वारा आय में वृद्धि के उद्देश्य से दुकानदारों को केवल भूमि का आवंटन किया गया था जिसमें व्यापारियों ने स्वयं के खर्च से संरचना निर्माण किया। निगम द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश के आलोक में दुकानदार निर्माण के अनुरूप निगम को टैक्स का भुगतान भी करते हैं। बावजूद इसके लाइसेंसधारी के निधनोपरान्त या परिवार के सदस्य के अलग होने की स्थिति में दुकानों के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। जबरदस्ती पौनल और पौनल पर अतिरिक्त ब्याज लगाकर, इसका

मांडर के बजरताड़ में हल-अरब बिरयानी का शानदार आगाज



संवाददाता । रांची

मांडर : मांडर प्रखंड के बजरताड़ में मंगलवार को हल-अरब बिरयानी नामक नए होटल का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। यह शुभ अवसर न केवल एक नए व्यवसाय की शुरुआत का प्रतीक बना, बल्कि स्थानीय समुदाय के लोगों के बीच आपसी सौहार्द और उत्साह का भी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। संचालक मकसूद आलम ने बताया कि हल-अरब बिरयानी में ग्राहकों को बेहतरीन गुणवत्ता और स्वाद वाली बिरयानी के साथ-साथ विविध लजीज व्यंजन परसेसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वाद और स्वच्छ वातावरण में पारिवारिक माहौल प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह के दौरान आए अतिथियों ने होटल के साज-सज्जा, स्वच्छता और स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करते हुए संचालक को शुभकामनाएं दीं।

ओबीसी छात्रों का हक किसी कीमत पर नहीं छीनने देंगे - एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष बिनय उरांव



संवाददाता । रांची

रांची । प्रदेश कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई झारखण्ड द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री बिनय उरांव के नेतृत्व एवं निदेशानुसार राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन इसलिए किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने ओबीसी छात्रवृत्ति का 60% हिस्से का फंड जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एनएसयूआई यह आंदोलन ओबीसी छात्रों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कर रही है। झारखण्ड के सभी जिलों में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त (डीसी) को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि ओबीसी छात्रवृत्ति फंड रिलीज के मुद्दे को केन्द्रीय कल्याण मंत्री, केन्द्रीय सरकार, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संज्ञान में तुरंत लाया जाए, ताकि छात्रों को उनका हक मिल सके। रांची जिला में यह आंदोलन एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष श्री सतीश केशरी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव पवन नाग और रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष कैफ अली अपने विश्वविद्यालय समिति के पदाधिकारियों के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। महानगर अध्यक्ष सतीश केशरी ने स्पष्ट कहा कि अगर केन्द्र सरकार ने शीघ्र ही ओबीसी छात्रों का हक नहीं दिया, तो एनएसयूआई पूरे झारखण्ड में चक्का जाम आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत एकदिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला



संवाददाता । रांची

रांची । गभर्धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत एकदिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन आईपीएच सभागार नामकुम में आयोजित किया गया । कार्यशाला में सभी जिला से एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन एवं असिस्टेंट नोडल ऑफिसर (डडउठउठ) एवं अन्य पदाधिकारी प्रतिभागियों के रूप में शामिल हुए । कार्यशाला की शुरुआत में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ सिद्धार्थ सान्याल के द्वारा गभर्धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (डउ-डउउठ अउ३) के प्रति प्रतिभागियों को जागरूक किया गया । साथ ही कहा कि हर जिला में उज्ज्व (उर २३३ अरि, २इर, २इर ३डी) की मॉनिटर हर 2 महीने पर किया जाना है । इसके लिए सभी जिला के उपायुक्त के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हर दो महीने के अंतर्गत बैठक आयोजित करें । वही प्रखंड स्तर पर भी एक टीम होनी चाहिए जो प्रखंड स्तर पर अल्ट्रासाउंड मशीन का समय-समय पर निरीक्षण करें । आज हमारे राज्य में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, कुछ लोग दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन करके यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं जो सही नहीं है, ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र एवं टेक्नीशियन का पता करके उन पर समुचित कर्वाई की जानी चाहिए । सभी जिला अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक को इम्पेन्ड करने के पहले सही तरीके से जांच कर ले कि उन पर पहले से डडउठउठ के तहत कोई कोर्ट केस तो नहीं है । साथ ही यदि कोई व्यक्ति क्लिनिक खोलने हेतु आवेदन करता है तो उसे 70 दिनों के अंदर अनुमति (परमिशन) दे देना है और यदि किसी कारणवश रिजेक्ट किया जाता है तो उसका उचित कारण देना होगा । कार्यशाला में डॉ वैभव पाठक (छीं डुल्लर ४) रेलेर, डउउठ रीडुल्लर, टडउठर) वरुअल माध्यम से जुड़कर प्रतिभागियों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के विभिन्न आयामों के बारे में बताया । साथ ही कहा कि यदि किसी गर्भवती महिला का अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए । डॉ सत्यजीत कुमार (स्टेट नोडल ऑफिसर, नई दिल्ली) ने वरुअल मोड से कार्यशाला में जुड़ कर इस अधिनियम के तहत केस स्टडीज पर चर्चा किया ।

यूपी सरकार के द्वारा बरेली में, Love Mohammad के पोस्टर को लेकर मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने के खिलाफ देश के महामहिम, भारत के राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक खुला पत्र

संवाददाता । रांची
रांची । श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रीय भवन भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: उत्तर प्रदेश में "I Love Mohammad" पोस्टर लगाने के नाम पर मुस्लिम युवकों और धार्मिक गुरुओं पर कार्रवाई, निरन्तरी और बुलडोजर की घटनाओं पर संज्ञान लेने तथा हस्तक्षेप करने के संबंध में। माननीय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं तनवीर अहमद झारखण्ड सहित देश सभी सभ्य समाज एवं देश के करोड़ों मुस्लिम समाज की जानिब से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय के साथ किए गए अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक कार्यों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, 5 सितम्बर 2025 को ईद मिलादुन्बी के अवसर पर कानपुर में कुछ मुस्लिम युवकों ने हक छड़्की टैग्लिखे पोस्टर लगाए, जो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की भावना का प्रतीक था किन्तु कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा इस पोस्टर पर आपत्ति जताई गई, इस आपत्ति पर पुलिस ने 10-15 युवकों पर एफआरआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के मुस्लिम समाज में गहरी बेचैनी और



नाराजगी पैदा कर दिया। जिस पैगम्बर को शांति, भाईचारा और ईंसानियत का पैगाम देने के लिए ईश्वर ने पूरी मानवता के बीच भेजा, उनकी मोहब्बत का इजहार अपराध कैसे माना जा सकता है? यह प्रश्न हर संवेदनशील नागरिक के मन में उठने लगा। इसके बाद देशभर में शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुए। लोग एक छड़्की टैग्लिखे के पोस्टर लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसी क्रम में 26 सितम्बर 2025 को बरेली में जुम की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। मैं मादता हूँ कानूनी तौर पर बिना परमिशन के विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं था, लेकिन वहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, कुछ को एनकाउंटर में घायल किया गया और बड़ी संख्या में लोगों के

घरों व दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब बनी जब बरेली निवासी देश के महारू इस्लामी विद्वान मौलाना तौकीर रजा साहब और उनके परिवार को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर-दुकान भी तोड़ दिए गए। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में भय और तनाव का वातावरण बन गया। सरकार ने अनुचित कर्वाइ करते हुए बरेली में मुसलमानों की 1300 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को जप्त कर ली गई।

विधायक राज सिन्हा ने बस स्टैंड को लेकर फैलाई जा रहे अफवाह पर कहा, जनता जहां चाहेगी बस स्टैंड वहीं बनेगा

धनबाद, संवाददाता

विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने जगजीवन नगर स्थित आवासीय कार्यालय में इंटर स्टेट बस टर्मिनल एवम बरटांड बस स्टैंड को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम एवम उठापोह को दूर करते हुए प्रेस वार्ता की. धनबाद स्थित बरटांड बस स्टैंड को लेकर विधायक राज सिन्हा का स्पष्ट बयान - बस स्टैंड वहीं रहेगा जहाँ वर्तमान में है और यह काफी पहले से तय है. धनबाद के बरटांड बस स्टैंड को लेकर बौते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही हैं. जिससे आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने आवासीय कार्यालय, जगजीवन नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर स्थिति को



स्पष्ट किया। विधायक राज सिन्हा ने कहा: बरटांड में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के लिए पहले से ही लगभग 22 एकड़ भूमि उपलब्ध है। ऐसे में जब पूरी जमीन बरटांड में है, तो फिर कतरास में केवल 12 एकड़ भूमि स्थानांतरित करने की क्या आवश्यकता है? विधायक ने बताया कि उन्होंने इस विषय पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन से 20-22 दिन पूर्व ही विस्तार पूर्वक से चर्चा की है।

इस बातचीत के क्रम में उपायुक्त ने न केवल मामले को गंभीरता से लिया, बल्कि यह भी आश्वासन दिया की, 11 अक्टूबर 2025 को वे स्वयं बरटांड बस स्टैंड का स्थल निरीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार उसे विकसित किया जायेगा. पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि बस स्टैंड वहीं रहेगा जहाँ वह वर्तमान में स्थित है। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि, धनबाद की जनता की भावना सर्वोपरी है और बिल्कुल उसी

अनुरूप कार्य होगा. विधायक श्री सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा: मैं धनबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बस स्टैंड को कहीं और लेके नहीं जाया जा रहा है जहाँ हैं वहीं रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं, वे केवल जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की

सुविधा और राय के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा श्री सिन्हा ने अंत में कहा: धनबाद के विकास में किसी भी तरह की राजनीति या अफवाह को कोई जगह नहीं है। जनता की आवश्यकता, भावना और सुविधा सर्वोपरि है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बरटांड बस स्टैंड का स्थान नहीं बदलेगा बल्कि वहीं रहेगा जहाँ वह वर्तमान में है। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि, जनता के हित और सुविधा के लिए पहले भी संघर्ष और आंदोलन किया है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः करने को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हूँ। प्रेस वार्ता में धनबाद महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय, जिला महामंत्री मानस प्रसून, जिला मंत्री सह मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा उर्फ कुमार अमित, जिलामंत्री रीता यादव, मंडल अध्यक्ष राजाराम दत्ता, किशोर मंडल, मनोज मालाकार, निर्मल प्रधान, मदन तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे।

विधानसभा समिति ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा



धनबाद, संवाददाता

झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने सभापति सह महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में तथा समिति के सदस्य सह विधायक कांके सुरेश कुमार बैठा, विधायक जामा डॉ लुईस मरांडी एवं विधायक बाड़कागांव रोशन लाल चौधरी की उपस्थिति में सक्रिय हाउस में वन, नगर निगम, आपूर्ति, झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, परिवहन, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा,

उद्योग केन्द्र, उत्पाद, खनन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूमि-संरक्षण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, कौशल विकास, खेल, पर्यटन, श्रम, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल 1 एवं 2, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल (यान्त्रिक), पथ प्रमण्डल, भवन प्रमण्डल, लघु सिंचाई, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चिरकुंडा नगर परिषद सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक से पहले उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने समिति के सभापति तथा सदस्यों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी

विकास पालीवाल, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, नगर आयुक्त श्री रवि राज शर्मा, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाबरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिया, सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

छठ महापर्व में छठ वर्तियों को ना हो कोई परेशानी : नीरज मंडल

रामगढ़, संवाददाता

छठ महापर्व आने से पूर्व छवनी परिषद अंतर्गत सभी छठ घाट की साफ सफाई छवनी परिषद रामगढ़ के छवनी अधिशासी अधिकारी श्री अनंत आकाश के निर्देश पर सफाई इंस्पेक्टर नितिन ठाकुर के निगरानी में सभी छठ घाटों पर हो रही है. उक्त बाते आजसू पार्टी रामगढ़ नगर सचिव नीरज मंडल ने कही और साथ ही छवनी परिषद के उद्भूत अनंत आकाश और सहयोगी सभी सफाई कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी लोग जिस तरह से प्रत्येक दिन हर एक गली मोहल्ला में सभी छठ घाटों पर हो रही है, वह प्रशंसा के पात्र हैं" और उनसे आग्रह किया कि छठ महापर्व से पूर्व सभी छठ घाटों का और विशेष करके दामोदर नदी, बिजुलिया तालाब, हर हरी नदी, जहां छठ वर्तियों के साथ-

श्रद्धालु वृहद रूप में शामिल होते हैं वहां नियमित रूप से साफ सफाई और आने जाने वाली मार्ग में पोल में लाइट लगवाई जाए और खराब लाइट को अंधिलान्वित ठीक किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या की सामना छठ वर्तियों या श्रद्धालुओं को ना हो सके, इसका विशेष ध्यान भी आप सभी रखें" इस मौके पर आजसू पार्टी रामगढ़ नगर सचिव नीरज मंडल, छवनी परिषद रामगढ़ के सफाई इंस्पेक्टर नितिन ठाकुर के मौजूदगी में सफाई कर्मियों के सुपर वाइजर नव रंजन राम, लाल बाबू राम, भोला राम, गुलचंद राम, बिदू राम, भरत राम, भीमा राम, अनिल राम, प्रेम नाथक, शेखर राम एवं सफाई कर्मियों में लव राम, सनी राम, मिदू राम, कार्तिक कुमार, जीनू राम, प्रदीप राम, सिकंदर राम, राजा कुमार, नीरज राम, रंजीत राम, अजय राम, सफाई कर्मी मौजूद थे

कतरास में बस स्टैंड बनने से प्रसिद्ध लिलोरी मंदिर पर्यटक स्थल को मिलेगा बढ़ावा : सूर्यदेव मिश्रा

कतरास, संवाददाता

बुधवार को भारतीय जनता पार्टी कतरास मंडल कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कतरास में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को लेकर बयान जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कतरास मंडल अध्यक्ष सूर्य देव मिश्रा ने की। सूर्यदेव मिश्रा ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले कतरास के लिलोरी मंदिर के समीप अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने को लेकर निर्णय हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। बस स्टैंड कतरास में बनने की चर्चा प्रकाश में आने पर यहाँ के लोग काफी खुश हैं। धनबाद की जनता में भी खुशी की लहर है। क्योंकि



कतरास का प्रसिद्ध लिलोरी स्थान न केवल एक मंदिर रहा बल्कि मंदिर के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित होता जा रहा है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड कतरास में बनने से पर्यटक स्थल को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बगल से एड्ट लाइन भी गुजरी है जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। यह स्थल शांति और सुरक्षित भी है। कहा कि कोई भी बड़ा

संस्थान उपयुक्त जमीन व सुरक्षित जगह देखकर ही बनाया जाता है। ऐसे संस्थान घनी आबादी व शहर से दूर ही बनता है। जैसे यूनिवर्सिटी, बी टैक कॉलेज, पोलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि शहर की भीड़ भाड़ से दूर में ही बनाया जाता है। लेकिन कुछ राजनितिक दल को बूटभैये नेता अपने निजी हित को साधने के लालच में इसका विरोध कर

उप विकास आयुक्त ने किया गोला प्रखंड का दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

रामगढ़, संवाददाता

बुधवार को जिले के उप विकास आयुक्त श्री आशीष अग्रवाल ने गोला प्रखंड का दौरा किया इस दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया। दौरे के क्रम में उप विकास आयुक्त ने झारखंड सरकार द्वारा संचालित आईटीआई गोला में आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। मौके पर उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए आईटीआई कॉलेज का पूरा लाभ लेने की सभी से अपील की। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी सभी के साथ साझा की। कार्यशाला के दौरान उप विकास आयुक्त ने अर्थव्यथियों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आईटीआई गोला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आईटीआई गोला के उपरत उप विकास आयुक्त ने हारुबेड़ा क्षेत्र में डीएमएफटी मद से निर्मित सड़क का निरीक्षण कर सड़क की गुणवत्ता आदि का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। दौरे के क्रम में उप विकास आयुक्त के द्वारा



हारुबेड़ा क्षेत्र में जेएसएलपीएस द्वारा संचालित मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट, गेंदा फूल उत्पादन कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ज्यदा से ज्यदा ग्रामीणों को उक्त कार्यों में शामिल करते हुए उन्हें लाभाभिव्यक्त करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त के द्वारा हारुबेड़ा क्षेत्र में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बागवानी योजना, कूप निर्माण, आवास योजना का निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया एवं ज्यदा से ज्यदा मानव विकास सृजित कर लाभुकों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए आवास योजना का कार्य समसम पूर्ण करने का निर्देश

दिया। दौरे के क्रम में उप विकास आयुक्त के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला का निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। मौके पर उन्होंने केंद्र के माध्यम से आम जनो को उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही केंद्र पर दवाइयों की उपलब्धता जांच सुविधाओं आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जांच के दौरान पाई गई कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला डॉ सुधा वर्मा सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मनरेगा श्री विजय कुमार डीएमएफटी टीम लीड सुकांतो टेटे, डीएमएफटी टीम के सदस्यों सहित अन्य उपस्थित थे।

बोकारो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर करें कार्य : उपायुक्त



बोकारो, संवाददाता

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, उद्यान, आत्मा और जेएसएलपीएस की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक परिवार को ऑन फार्मिंग और ऑफ फार्मिंग गतिविधियों से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि लाभुकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। एकल महिलाओं, विधवाओं और स्वयं सहायता समूहों को योजनाओं में प्राथमिकता देने को कहा गया।

उन्होंने कृषि विभाग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, झारखंड मिलेट मिशन, कृषक समृद्धि योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना व डिजिटल क्रॉप सर्वे में लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवंबर में धान कटनी महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत का सम्मान किया जाएगा। मत्स्य विभाग को तालाबों की मैपिंग और केज फिशिंग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। पशुपालन विभाग को गोदरी बैंक स्थापना और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य सौंपा गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग मिलकर कार्य करें तो बोकारो को आत्मनिर्भर जिला बनाया जा सकता है।

करगली में इनमोसा की 70वीं स्थापना दिवस मनी

बेरमो, संवाददाता

बुधवार को बेरमो कोयलांचल क्षेत्र के सीसीएल के बीएंडके एरिया के करगली गेट स्थित कल्याण मंडप में इनमोसा की 70 वीं स्थापना दिवस मनाई गई. सर्वप्रथम स्व जे के बनर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया. बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि आठ अक्टूबर 1956 को स्व जे के बनर्जी ने स्थापना की थी. कहा कि इनमोसा माइनिंग सुपरवाइजर के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। प्रबंधन के साथ हर कदम पर मसलन उत्पादन, सुरक्षा एवं गुणवत्ता पर ध्यान में रखते हुए कंपनी के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि इनमोसा को स्व बनर्जी एवं कई दक्ष खनन विद्वों ने लगन से सींचा एवं वट वृक्ष के रूप में तैयार किया। माइनिंग सुपरवाइजरों की किसी समस्या पर सुपरवाइजरों को किसी दूसरे संगठन के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संगठन के इतिहास



और पूर्वजों के बलिदान को नवीन सदस्यों के बीच रखा और कोल इंडिया स्तर और सी सी एल स्तर पर इनमोसा की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी लोग अपने आप को संगठित करें। बीएंडके क्षेत्रीय सचिव डी पी मौर्या और दोरी क्षेत्रीय सचिव पवन सिंह ने कहा कि इनमोसा अपने सदस्यों की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी. कार्यक्रम में बीएंडके, दोरी और कथारा क्षेत्र के सदस्यों ने बहू चढ़ कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएंडके क्षेत्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व संचालन खास

महल शाखा सचिव शैलेंद्र कुमार ने किया. मौके पर दोरी क्षेत्रीय अध्यक्ष तुलसी महतो, कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष नौशाद खान, सचिव बालेश्वर महतो सहित अवधेश कुमार, हेमंत चौहान, जयराम सिंह, हीरालाल रविदास, मदन सिंह, शशांक शेखर, सुधिशिर सिंह, निरंजन सिंह, प्रमोद सिंह, आनंद विक्वकर्मा, रोशन सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, मोहम्मद नौशाद, तन्मय दे, अजीत सिंह, अंगद सिंह, रोशन सिंह, बबन रजक, फ्रांसिस बास्के, नरेश महतो, डीमन पासवान, संतोष मंडल, विजय महतो, लव कुमार, राजेंद्र मंडल, विनोद शर्मा, सनातन हेन्रम आदि सैकंडो लोग उपस्थित थे।

उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक



रामगढ़, संवाददाता

उपायुक्त, रामगढ़ श्री फैज अक अहमद मुमताज के निर्देशानुसार बुधवार को उप विकास आयुक्त श्री आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। राज्य योजना अनावद्ध निधि अंतर्गत योजनाओं के चयन हेतु जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त

अनावद्ध निधि से कार्यान्वयन हेतु योजनाओं को रखा गया। जिसमें पीसीसी पथ निर्माण, सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठाण कार्य, पुल, पुलिया, बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, सामुदायिक भवन का निर्माण व अन्य योजनाओं जो माननीय एवं अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त हुआ है के संबंध में पारित करने हेतु विचार विमर्श की गई। उप विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि मोटर साइकिल के सहारे अवैध डिपूअंत तक और कोल फैक्ट्री में

अवैध कोयले की व्यावसाय बेरमो अनुमंडल में चल रहा धड़ल्ले से, प्रशासन मौन

प्रतिदिन सरकार को लाखों का राजस्व का हों रहे नुकसान कोयला तस्करी के भयाक्रांत से भरपूर है आम ग्रामीण

बेरमो, संवाददाता

बेरमो अनुमंडल थाना क्षेत्र के कथारा, जारंगडीह, बोकारो थर्मल, गोमिया, पेंक-नारायणपुर, नावाडीह में विगत एक माह से अवैध कोयला का व्यावसाय खुलेआम धड़ले से चल रहा है। पेंक-नारायणपुर, गांधीनगर, बोकारो थर्मल और बेरमो थाना क्षेत्र के सीमांकन जंगल में दर्जन भर से अधिक अवैध उत्खनन गुफा बना है जहाँ से प्रतिदिन बीस-पच्चीस ट्रेक्टरों और सौ से अधिक मोटर साइकिल के सहारे अवैध डिपूअंत तक और कोल फैक्ट्री में



पहुँचाया जाता है। यहाँ से रात की अंधेरी में ट्रकों और वैन के सहारे बाहर की मंडियों तक पहुँचायी जा रही है। इतनी गाड़ियाँ चलने के बावजूद प्रशासन अगोचर का चरितार्थ बना हुआ है। उक्त अवैध कोयला की कारोबार से प्रतिदिन सरकार की राजस्व में लाखों रुपये की क्षति हो रही है। बावजूद सरकार के प्रशासन तंत्र तस्करी को

करवाई न कर मनोबल बढ़ाने की कार्य कर रही है। उक्त स्थलों से हो रही है कोयला चोरी अवैध कोयला की चोरी जारंगडीह रेलवे साइडिंग, कथारा, कुसुमडीह, सीसीएल के बीएंडके कथारा दोरी और गाँवदुपुर खदान से और खाशमहल फेस-टू के

खदानों से एवम पेंक-नारायणपुर थाना के सोतापानी, सिझवाखलार, बेरमो थाना के चरकपनिया, रसबेड़ा और बोकारो थर्मल के फेस-टू बंद खदान से अवैध उत्खनन कर खुलेआम ढुलाई हो रही है। विभिन्न वाहनों से निम्न दरों से होती है वसुली

15 से 20 वर्ष पहले नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट भाकपा माओवादी संगठन का सुरक्षित जोन के रूप में प्रशासन और अन्य तंत्रों के द्वारा माना जाता था, लेकिन अब के अनुसार एक करोड़ से अधिक रूपए की वसुली केवल पेंक-नारायणपुर नारायणपुर और नावाडीह थाना क्षेत्र से हो रही है। तब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम किसकी गरम कर रहा है, अगर प्रशासन के जेब में नहीं पहुँच रहा है, तो सुई गिरने की आवाज प्रशासन को सुनाई दे देती है, लेकिन 40 से 45 टन कोयला ढुलाई करने वाले ट्रकों की आवाज सुनयी क्यों नहीं देती है। इधर ग्रामीणों की बातें माने तो सड़क में चलने वाले आम जनता काफी भयभीत होकर चलते हैं, अब तक

दर्जन भर लोग दुर्घटना से घायल हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है मां जगदम्बा कॉल फैक्ट्री - नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पेंक-नारायणपुर थाना अंतर्गत रामामहलिया में अवस्थित मां जगदम्बा नामक कॉल फैक्ट्री द्वारा भट्टी में पोड़ा कम और खुले मैदान में अधिक पोड़ा बनाया जा रहा है। जिससे पर्यावरण को दूषित खुले चुनौती के साथ कर रहा है। फैक्ट्री के महज पाँच सौ मीटर की दूरी पर अवस्थित रामामहलिया और गिरदरपका गांव दिन का उजाला में भी अंधेरा में दुबकने का विवस हो जा रहा है, ग्रामीणों की आवाज दबावों की चोली बंद कर दे रही है।

भारत पर गूगल का 10 अरब डॉलर का दांव



नई दिल्ली, एजेंसी। गूगल भारत में अपना पहला और देश के डिजिटल हिस्से में सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है। कंपनी 10 अरब डॉलर (लगभग 88, 730 करोड़ रुपये) की लागत से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1 गीगाबीट क्षमता वाला एक विशाल डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करेगी। यह परियोजना एशिया में अब तक की सबसे बड़ी होगी और इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें गूगल और उसकी सहायक कंपनियां वर्तमान में 11 देशों - अमेरिका, ताइवान, जापान, सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और इटली में 29 स्थानों पर डेटा सेंटर संचालित करती हैं। डेटा सेंटर क्लस्टर विशाखापट्टनम जिले के अडविवायम और तारुलवाडा गांवों तथा पड़ोसी अनाकापाली जिले के रामबिल्ली गांव में तीन अलग-अलग कैम्पस में बनाया जाएगा। इसके लिए तीन उच्च-क्षमता वाली खबरनीन केबल लगाई जाएंगी, जिनके लिए विशेष केबल लॉजिंग स्टेशन और मेट्रो फाइबर लाइनों सहित उन्नत दूरसंचार ढांचा विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य विशाखापट्टनम में मुंबई से दोगुना खबरनीन केबल नेटवर्क तैयार करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिसंबर 2024 में ही गूगल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस परियोजना के अंतिम रूप से मंजूरी मिलने की उम्मीद है और गूगल की टीम और राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश के बीच 14 अक्टूबर को इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस डेटा सेंटर क्लस्टर के जुलाई 2028 तक चालू हो जाने का अनुमान है। हालांकि, गूगल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह डेटा सेंटर क्लस्टर भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब का केंद्र बनेगा।

टाटा ट्रस्ट्स में मतभेद पर सरकार की पैनी नजर

नई दिल्ली, एजेंसी। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई 45 मिनट की बैठक में केंद्र सरकार ने टाटा समूह के टॉप लीडरशिप को सख्त संदेश दिया कि टाटा ट्रस्ट्स में स्थिरता बनाए रखें और आंतरिक विवादों को नियंत्रित करें ताकि उनका असर टाटा समूह पर न पड़े, जो देश का सबसे मूल्यवान व्यवसायिक समूह है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टाटा समूह के वार धरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोबल टाटा, वाइस चेयरमैन वेंकू श्रीनिवासन, टाटा समूह के चेयरमैन एन.



चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा। सरकार का मानना है कि टाटा ट्रस्ट्स के भीतर चल रहे मतभेद अगर समय पर सुलझाए नहीं गए, तो यह पूरे समूह की कार्यप्रणाली पर असर डाल सकते हैं। मंत्रियों ने कंपनी नेतृत्व को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं, जिसमें ऐसे ट्रस्टी को हटाना भी शामिल है जो समूह के सुचारु कामकाज में बाधा डाल रहा हो। बैठक में आरबीआई के निर्देशों पर भी चर्चा हुई, जिसमें टाटा समूह जैसी अपर्यार एनबीएफसी कंपनियों के पब्लिक लिस्टिंग का मुद्दा शामिल था। इसके साथ ही, समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक शापुरजी पल्लोनजी समूह के लिए लिक्विडिटी (नकदी की उपलब्धता) का रास्ता निकालने पर भी विचार हुआ।

सैमसंग इंडिया ने पंजाब में डिजिटल रिटेल एंड केयर प्रोग्राम शुरू किया

चुरूग्राम, एजेंसी। सैमसंग ने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित ग्रहकों और समुदायों की मदद के लिए अपना विशेष आपदा राहत और देखभाल कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रभावित इलाकों में केयर कैम्प लगाए जाएंगे, जहां परिवारों को जरूरी धरतू सामान, बुनियादी उपकरण और इमरजेंसी किट प्रदान करवाई जाएगी। वर्षों से, सैमसंग विभिन्न फलों के माध्यम से मुश्किल समय में लोगों का सहयोग करने के लिए आगे आया है। जैसेकि श्रीनगर में वेली ऑफ होप (2014) से लेकर केयर फॉर केरल (2018) और केयर फॉर महाराष्ट्र (2019) तक। इन पहलों से हजारों लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जीवन को फिर से संभारने में मदद मिली और मुश्किल हालात में उम्मीद की किरण मिली। पंजाब के गुरदासपुर में, जहाँ हाल ही में बाढ़ ने लोगों को निंदी प्रभावित की है, सैमसंग पहले ही अपने कॉन्टैक्ट सेंटर और सर्विस सेंटर के जरिए मदद के अनुरोध लेना शुरू कर चुका है। लोग लगातार केयर कैम्प में सहयता के लिए पहुंच रहे हैं। और जैसे-जैसे स्थानीय घोषणाएं और सूचनाएं आसपास के गांवों तक पहुंचेंगी, मदद के लिए आने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादातर रिक्वेस्ट पानी में डूबे स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीनों और रेफ्रिजरेटर से संबंधित हैं।

आईसीआरए का दावा भारत का गोल्ड लोन बाजार मार्च 2026 तक? 15 लाख करोड़ के स्तर को पार कर सकता है



नई दिल्ली, एजेंसी। देश का संगठित गोल्ड लोन बाजार मार्च 2026 तक 15 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने यह दावा किया है। आईसीआरए के अनुसार यह फलतः की उम्मीदों से एक साल पहले है। इस तेज वृद्धि का मुख्य कारण पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में आई लगातार बढ़ोतरी है, जो अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। आईसीआरए लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को-ग्रुप हेड (फाइनेंसियल सेक्टर रेटिंग्स) एएम कार्तिक ने कहा कि संगठित गोल्ड लोन

बाजार का आकार वित्त वर्ष 2027 तक और बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। एजेंसी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका कारण ऊंचे सोने के दाम और अमूर्तित ऋण उत्पादों में धीमी वृद्धि को माना गया है। यह आम तौर पर उभरी उधारकर्ताओं को लक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई कंपनियों का विविधीकरण और देश में उपलब्ध बड़ी मात्रा में प्री गोल्ड होल्डिंग्स इस वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक साबित होंगे।

सोने की ऊंची कीमतों से यह वृद्धि हुई सोने की ऊंची कीमतों के कारण हुआ है, लेकिन कोवैटरेल के रूप में रखे गए सोने का टन भार वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान 1.7 प्रतिशत की वक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से मामूली रूप से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान औसत ऋण आकार दोगुने से भी अधिक हो गया है, जबकि शाखाओं की संख्या में 3.3 प्रतिशत की धीमी सीएजीआर से वृद्धि हुई है।

बजट में बदलेगी सस्ते घरों की परिभाषा

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार आम लोगों को रहने का मिलासिला देने का काम आगे भी चालू रख सकती है। सूर्यो के मुताबिक, सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट में आम लोगों के लिए सस्ते मकानों की परिभाषा बदलने की योजना बना रही है। इसके तहत वर्तमान सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अभी 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों को अफोर्टेबल हाउसिंग यानी सस्ते घरों के वर्गीकरण के रूप में रखा गया है। लेकिन अब इसे महानगरों के लिए 55 लाख रुपये या फिर 60 वर्गमीटर किया जा सकता है। गैर महानगरों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 90 वर्गमीटर किया जा सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि अब आम आदमी को भी कम से कम 800-1000 वर्गफुट का दो या तीन बेडरूम, किचन और हाल यानी बीएफसी की जरूरत होती है। दरअसल, कई रियल्टी संस्थान लंबे समय से सरकार से



इस परिभाषा को बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका इस्तेफादा है कि 2017 में जब यह नियम बना था, तब से अब तक मकानों की कीमतों तो बढ़ी ही हैं, साथ ही मांगों भी जमकर बढ़ी हैं। ऐसे में अब 45 लाख रुपये में दूसरे स्तर के शहरों या तो तक कि दिल्ली और मुंबई के आस-पास जो शहर हैं, वहां भी मकान नहीं मिल रहे हैं। सूर्यो ने बताया, इस संबंध में कई रियल्टी संस्थानों ने हाल में सरकार से बात की है और सरकार इस बात पर तर्क लगा रही है। सरकार ने फरवरी में पेश बजट में आयाकर में भी यह तर्क दिया।

फिर आरबीआई की रेपो दर में एक फीसदी की बढ़ी कटौती और अब जीएसटी सुधार से लोगों को रहने तो मिली है, पर मकान खरीदने को अब भी रहने नहीं मिली है। रियल्टी संस्थानों का कहना है कि जीएसटी सुधार से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। सीमेंट पर जीएसटी कटौती से उनका क्या लेना देना है? अगर सीमेंट कंपनियां या डीलर कीमतें बढ़ाते हैं तो वे उनका फायदा तो दे देंगे, लेकिन यह घर खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। ऐसे में रियल्टी संगठन अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार कुछ राहत मिलेगी। सीधे तौर पर इस उद्योग को जीएसटी के सुधार से कोई फायदा नहीं हुआ है। रियल्टी कंसल्टेंट एनारके के अनुसार, भारतीय निवेश पर अमेरिकी टैरिफ से किफायती घरों की किल्ली प्रभावित होने की संभावना है। इससे छोटे व्यवसायों और उनके कर्मचारियों को आय प्रभावित होगी।

अगले साल 11 प्रतिशत तक बढ़ेगा वेतन



इंफ्रास्ट्रक्चर व एनबीएफसी सेक्टर में मिलेगी सबसे ज्यादा सैलरी हाइक

नई दिल्ली, एजेंसी। वेतन के मोर्चे पर सुनहरी तस्वीर सामने आ रही है। 2026 में वेतन 11 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। 2025 में 8.9 प्रतिशत वृद्धि से यह मामूली अधिक है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद मजबूत रोजगार बाजार को दर्शाता है। एजेंसी पीएलसी के अनुसार, 2026 में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक वेतन वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों 10.9 प्रतिशत वृद्धि कर सकती हैं। एनबीएफसी में 9.7, इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में 9.2 प्रतिशत, खुदरा में 9.6 और लॉजिस्टिक्स में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नौकरी छोड़ने की दर धीरे-धीरे कम होकर 2025 में 17.1 प्रतिशत हो गई है। 2024 में 17.7 और 2023 में 18.7 प्रतिशत थी। इसका मतलब कंपनियों कर्मचारियों को बनाए रखने और भविष्य के लिए एक मजबूत वर्कफोर्स बनाने के लिए क्षमता को बढ़ाने व डेवलपमेंट प्रोग्राम में निवेश करने में सक्षम हो रही है। जो कंपनियों अपनी पुरस्कार रणनीतियों को इन बदलावों के साथ जोड़ कर चलेंगी, वे शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छे स्थिति में होंगी।

आयोनोस ने वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल में एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस प्रदर्शित किया

लिस्बन, पुर्तगाल /नई दिल्ली। इंटरग्लोब एंटरप्राइस को एक कंपनी और एंटरप्राइस एआई में विश्व की आठवीं आयोनोस ने 7 से 9 अक्टूबर तक लिस्बन में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल में सिल्वर स्पॉन्सर के तौर पर प्रतिभाग करने की घोषणा की है। आयोनोस अपने प्रोफाइल एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस को प्रदर्शित करेगी जिसे विशेष रूप से विमान उद्योग में एआई संचालित परिवर्तन को निर्धारण रूप से अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण आयोनोस का इंटरलिमेंट प्लेटफॉर्म होगा जो विमान उद्योग के लिए खर्चित लागू करने के उद्देश्य से पूर्व एकीकृत और पूर्व प्रशिक्षित एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है। आयोनोस का लक्ष्य अधिक कुशल कार्यप्रवाह को गति देना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और विमान कर्मचारियों को एआई की संभावना का पूर्ण फेहल करने में मदद करना है जबकि वे यात्रकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़े रहें और आंतरिक परिवर्तनों को संभाल सकें। आयोनोस के सह संस्थापक और वाइस चेयरमैन सांजी गुनानी ने कहा, आयोनोस विमान कर्मचारियों को ऐसे एजेंटिक एआई उत्पाद और सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने की अनूठी स्थिति में है।



सोना पहली बार 1.25 लाख के पार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त



बैंकों ने एनबीएफसी की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज की

वित्त वर्ष 24-25 के दौरान, स्वर्ण ऋण लगभग 26 प्रतिशत की सीएजीआर से विस्तारित हुआ। यह मार्च 2025 तक 11.8 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया। बैंकों ने एनबीएफसी की तुलना में थोड़ी तेज वृद्धि दर्ज की। इससे समग्र संगठित बाजार में बाद की हिस्सेदारी में गिरावट आई। मार्च 2025 तक, बैंकों की कुल संगठित स्वर्ण ऋण बाजार में लगभग 82 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि शेष 18 प्रतिशत हिस्सेदारी एनबीएफसी के पास थी। एनबीएफसी की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से घटकर अब 2025 में 22 प्रतिशत हो गई है, जो इस क्षेत्र में बैंकों की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। आईसीआरए के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जून 2025 तक कुल एनबीएफसी गोल्ड लोन प्रबंधनाधीन परिसंचिका (एयूएम) 2.4 ट्रिलियन रुपये थी।

नई दिल्ली, एजेंसी। करवाचौथ पर सोने-चांदी के जेवर गिफ्ट में देने के लिए अब भी बार सोना पड़ेगा। 10 अक्टूबर को करवाचौथ है और उससे पहले आज सोने-चांदी की कीमतें सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक बार फिर नए ऑल टाइम पर हैं। आज 8 अक्टूबर को सोना एक इंच के भी 1832 रुपये महंगा हो गया है जबकि, चांदी के भाव में 1345 रुपये की उछाल दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 125452 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 155306 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 121799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, मंगलवार को यह बिना जीएसटी 119967 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 149438 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 150783 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आइबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अक्टूबर के महज 6 कारोबारी दिनों में सोना 6450 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 8349 रुपये का उछाल आया। इस साल सोना अबतक 46059 रुपये और चांदी 64766 रुपये महंगी हो चुकी है। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1824 रुपये महंगा होकर 121311 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 124950 रुपये हो गई है। अभी इसमें मैकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1678 रुपये उछलकर 111568 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 114915 रुपये है। आज 18 कैरेट गोल्ड 1374 रुपये की तेजी के साथ 91349 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।

अनिल अंबानी-आरकोम को हाईकोर्ट से झटका खातों को धोखाधड़ी में वर्गीकृत करने वाला एसबीआई का आदेश वैध

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह एक तर्कसंगत आदेश था और इसमें कोई न्यायिक खामोशी नहीं थी। न्यायमूर्ति रेवती गंधी डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने 3 अक्टूबर को एसबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका खारिज कर दी थी। फेसले को एक प्रति मंगलवार को सामने आई। इसमें कहा गया कि अंबानी को याचिका में कोई दम नहीं है, क्योंकि 13 जून 2025 के एसबीआई आदेश में कोई खामोशी नहीं थी। अदालत ने उद्योगपति को इस दलील पर विचार नहीं किया कि आदेश को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। अंबानी ने



अपनी याचिका में दलील थी कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और प्रारंभिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मास्टर निर्देशों के तहत उपलब्ध अधिकार, जिसके तहत एसबीआई ने अपना आदेश पारित किया, प्रतिनिधित्व करने का है, न कि व्यक्तिगत सुनवाई का। अदालत ने कहा कि अंबानी ने पिछले साल एसबीआई को ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया था और जब अंतिम पत्र का कोई जवाब नहीं आया तो बैंक ने खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का आदेश पारित कर दिया।

अब नहीं चलेगा फर्जी पैन और बेनामी सौदों का खेल, विभाग खंगालेगा रजिस्ट्री रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। बहिसाब संगति व बेनामी लेनदेन पर रोक लगोगी। आयकर विभाग संगति रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड की जांच करने की योजना बना रहा है। हजारों संगति सौदे अधिकार अधिकारियों की नजर से ओझल होने की आशंका है। रिपोर्टिंग में जानबूझकर की गई चूक और संगति के दस्तावेजों में खरीदारों-विक्रेताओं के फर्जी या भ्रामक पैन के कारण कई लेन-देन विभाग की नजर से ऐसे दोसे बच रहे हैं। संगति रजिस्ट्रार को 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संगतियों की खरीद और बिक्री का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें संगति पत्र रजिस्ट्रार कार्यालयों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके यह सुनिश्चित करते हैं कि सौदे की रिपोर्ट न की जाए या गलत पैन या नाम दर्ज कर दिए जाएं। इससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। उच्च मूल्य वाले रियल एस्टेट



लेनदेन का उपयोग लंबे समय से काले धन को जमा करने के एक माध्यम के रूप में किया जाता रहा है। इसे आसकर फर्जी संस्थाओं के माध्यम से छुपाया जाता है। इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए संगति पंजीकरण से पहले सभी पक्षों के लिए पैन और आधार का अनिवार्य है-सत्यापन एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह कदम नकली या गलत पैन या आधार विवरणों के उपयोग को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि संगति के रिकॉर्ड वास्तविक स्वामित्व को दर्शाते हैं।

स्टील एक्सचेंज इंडिया ने अधिक अनुकूल शर्तों पर 350 करोड़ की पुनर्वित्त सुविधा सुनिश्चित की

विशाखापट्टनम, एजेंसी। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड दक्षिण भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी एकीकृत स्टील निर्माताओं में से एक और 'सिंहद्वी टीएम्टीओ क्लब' के तहत टीएम्टी रिहायश में एक विरचयनीय नाम, ने गैर-परिवर्तनीय डिमेंसिंस और एक टर्म लोन की पूर्ण भुगतान/रिडेम्पशन के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने करीब कम ब्याज दरों पर पुनर्वित्त सुनिश्चित किया है। 30 सितंबर 2025 को, कंपनी ने कोटक महिंद्रा इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड, अक्सिसओ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कोटक क्रेडिट ऑपरेटिंग लिमिटेड फंड सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के एक संग से 350 करोड़ की पुनर्वित्त सुविधा की मंजूरी प्राप्त की है। इसमें से 150 करोड़ पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और इसका उपयोग मौजूदा

उच्च लागत वाले एनसीडीएस और टर्म लोन की पूर्ण भुगतान के लिए किया गया है। शेष 200 करोड़ 10 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले आवश्यक अनुबंधों के सबजेक्ट वर्तमान धारकों से बकाया एनसीडीएस खरीदने के लिए वितरित किए जाएंगे। उपरोक्त पुनर्वित्त सुविधाओं के साथ, कंपनी ने 30 सितंबर 2025 को 25 करोड़ के टर्म लोन का पूर्ण भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया, 84.30 करोड़ के सुरक्षित अनलिस्टेड एनसीडीएस का पूर्ण पूर्व-रिडेम्पशन किया और 32.35 करोड़ के सुरक्षित लिस्टेड एनसीडीएस का आंशिक रिडेम्पशन किया, जिससे लिस्टेड एनसीडीएस की बकाया मूलधन राशि 198.56 करोड़ रह गई। इस बकाया राशि को कोटक क्रेडिट ऑपरेटिंग लिमिटेड फंड 10 अक्टूबर 2025 या उससे पहले अधिग्रहित करेगा।



क्या आप इंसोमनिया के साथ ऑक्सिट्रिवटव स्लीप एपनिया से भी जूझ रहे हैं

एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में 'इंसोमनिया' और 'ऑक्सिट्रिवटव स्लीप एपनिया' के कॉन्टैक्ट यानी 'कोस्मिया' को ज्यादा घातक करार दिया गया है। शोधकर्ताओं ने इसका सामना करने वाले लोगों में हृदयरोगों से मौत का खतरा कई गुना ज्यादा पाया है।

सबसे आम बीमारियां

विशेषज्ञों के मुताबिक 'इंसोमनिया' और 'ऑक्सिट्रिवटव स्लीप एपनिया' नौद से जुड़ी सबसे आम बीमारियां हैं। वैश्विक स्तर पर 10 से 30 फीसदी आबादी के इनके शिकार होने का अनुमान है। बड़ी संख्या में ऐसे पीड़ित भी मौजूद हैं, जिन्हें वेनो की शिकायत होती है।

क्या हैं प्रमुख लक्षण

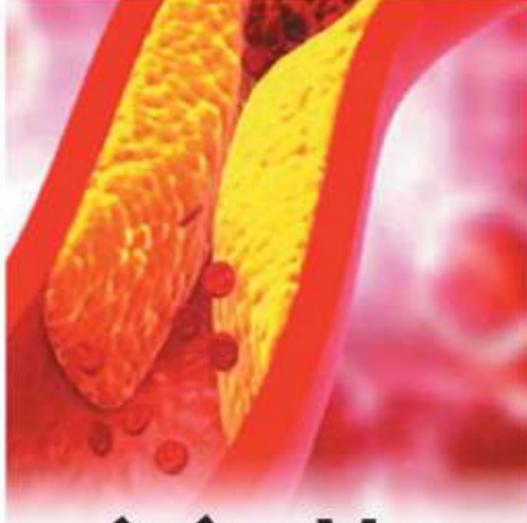
फिलडर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि 'इंसोमनिया' में व्यक्ति को सोने में दिक्कत, बार-बार नींद टूटने और जल्द आंख खुलने की शिकायत सताती है। वहीं, 'ऑक्सिट्रिवटव स्लीप एपनिया' में खरोंटे, मला चोक होने और सांस लेने में तकलीफ की समस्या आम है।

हाइपरटेंशन

डॉ. बेरिथियन लेवल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने नौद की बीमारियों से जूझ रहे 5000 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य डाटा का विश्लेषण किया। इस दौरान 'कोस्मिया' के शिकार लोगों में हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) का खतरा दोगुना मिला। उनमें हृदयरोगों की अंशका भी 70 फीसदी ज्यादा पाई गई।

असामयिक मौत का खतरा

कोस्मिया से पीड़ित लोगों के वयत से पहले मौत का शिकार होने का जोखिम भी 47 फीसदी अधिक दर्ज किया गया है। चूंकि, 'इंसोमनिया' और 'ऑक्सिट्रिवटव स्लीप एपनिया' का कॉन्टैक्ट ज्यादा जानलेवा है, इसलिए एक का सामना कर रहे मरीज में दूसरे के लक्षणों पर भी गौर फरमाना जरूरी है।



कोलेस्ट्रॉल कम करेगा अमरूद

कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं जिसकी वजह से उन्हें दिल से जुड़े विभिन्न रोगों का सामना करना पड़ रहा है। यह मौम की तरह घिपघिपा पदार्थ होता है, जो खून की नसों में पाया जाता है। इसका निर्माण आपके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों से होता है, साथ ही आपका लीवर भी इसे बनाता है।

शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के नुकसान यह है कि इससे खून की नसों ब्लॉक हो सकती है जिससे ब्लड फ्लो बाधित हो सकता है और आप के लिए दिल के विकारों के साथ दिल के दौरा और स्ट्रोक का जोखिम पैदा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय क्या हैं? नसों में

जमा गंधा कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे अच्छा तरीका हल्दी इड्रट और एक्सरसाइज है। हालांकि मेडिकल में कई दवाएं कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करती हैं। इनके अलावा आप अमरूद जैसे फाइबर से भरपूर फलों को खाकर भी इसे कम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। एक रिसर्च के अनुसार, सर्दियों का मौसम है और इन दिनों अमरूद खूब बिक रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए आपको अमरूद का सेवन करना चाहिए। यह फल आसानी से कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के विकास को बढ़ावा देता है।

कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है अमरूद

इसी अध्ययन में इस बात के प्रमाण हैं कि फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स, फल और सब्जियां खाने से शरीर में जमा फैट को कम

करने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं फाइबर से ब्लड लिपिड को कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है।

रिसर्च में हुआ खुलासा

कोलेस्ट्रॉल में अमरूद के फाइबर के लिए एक अध्ययन किया गया जिसमें प्रभागियों ने 12 हफ्ते तक अमरूद का सेवन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इतने दिनों के बाद हाई डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, सीरम कुल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर (9.0/8.0 मिमी एचजी) तक कम हो गया था।

अमरूद के पोषक तत्व

देखने में यह एक अमरूद फल है लेकिन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए इसके बड़े फायदे हैं। यह आहार फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सिडेंट और कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर है।

पत्ते भी हैं फायदेमंद

बेशक आपको अमरूद परंपद न हो लेकिन इसके फायदे हेरान करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि इस फल के पत्ते, छाल और फूल भी कई गुणों से भरे हैं। इनका पारंपरिक रूप से कई बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इन आसान उपायों से मिनटों में दूर होगा सिरदर्द

गर्म पानी में नींबू का रस

आप फटाफट से तैयार होने वाला यह नुस्खा आजमा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ यह करना है कि 1 गिलास में गर्म पानी लीजिए और उसमें नींबू का रस डालकर पी लें। फिर देखिएगा आपको सिर दर्द से कितनी जल्दी राहत मिलती है। कई बार पेट में गैस बनने से भी सिर दर्द होने लगता है। उस स्थिति में भी यह घरेलू उपाय बेहद ही कारगर माना गया है।

लैवेंडर का तेल

लैवेंडर के तेल को सूधने से आपको सिर दर्द की समस्या से बेहद आराम मिलता है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार लैवेंडर का तेल माइग्रेन के लक्षणों को भी ठीक करने में मदद करता है। एक टिशू पैपर पर लैवेंडर के तेल की कुछ बूँदें डाल लें और फिर उस पैपर को सूँघ लें।

लौंग का इस्तेमाल

तंदे पर लौंग को कुछ कलियों को गर्म कर लीजिए। इन गर्म हो चुकी लौंग की कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। खेड़ी-थोड़ी देर पर इस पोटली को सूँघते रहिए। आप पार्श्वे कि

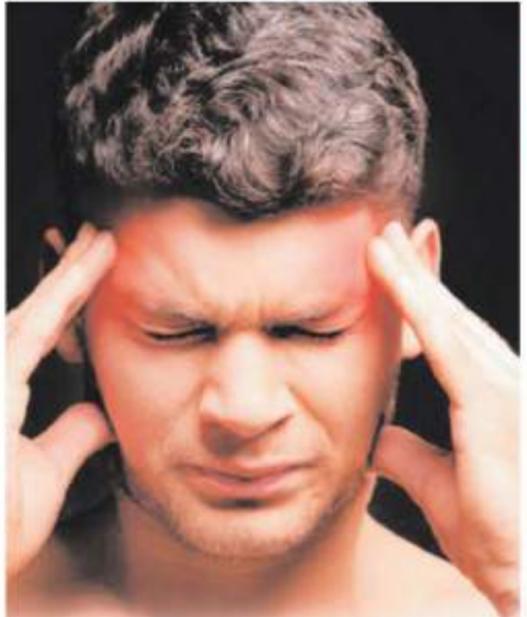
सिर का दर्द कम हो गया है। लौंग में दर्द खत्म करने के गुण होते हैं।

एक्यूप्रेशर के द्वारा

सातों से लोग सिर दर्द में राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते आ रहे हैं। सिर दर्द होने की स्थिति में आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने ले आए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। ये प्रक्रिया दोनों हाथों में दो से चार मिनट तक दोहराइए।

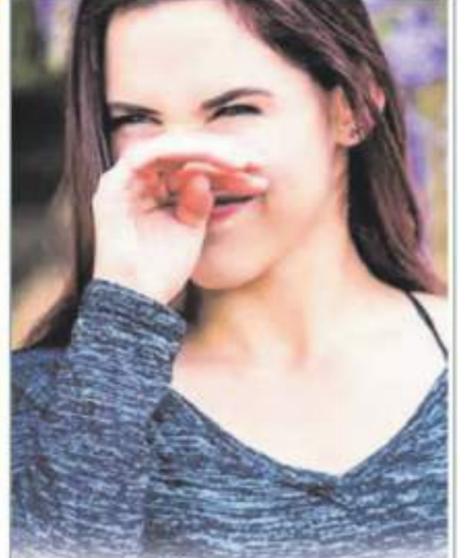
तुलसी

तुलसी मांसपेशियों को आराम देने की तरह काम करती है। थकी हुई मांसपेशियों के कारण होने वाले सिर के दर्द का इलाज करने में तुलसी बेहद लाभदायक होती है। इसके साथ ही इसमें आराम देने और एनाल्जेसिक के प्रभाव भी मौजूद होते हैं। एक कप पानी में सबसे पहले तीन या चार तुलसी की पत्तियों को कुछ मिनट तक उबालने के लिए रख दें। आप इसमें कुछ मात्रा में शहद भी मिलाकर चाय को पी सकते हैं।



सिर दर्द स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है जो कम्प्लेक्स कभी-न-कभी हर किसी को होता रहता है। आम तौर पर सिर दर्द की समस्या गर्मी के दिनों में ज्यादा परेशान करती है। यह इतना तेज होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सिर दर्द को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी में कई तरह की दवाइयाँ

उपलब्ध हैं, लेकिन हर बार इसके लिए दवाइयाँ लेना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। विशेष रूप से एलोपैथी की पैन किलर का प्रभाव शरीर की दूसरी बीमारियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करके सिरदर्द को शिकायत को दूर किया जा सकता है।



एलर्जी के कारण होती है नाक में खुजली

मौसम बदलने से नाक में एलर्जी के कारण खुजली महसूस होने लगती है। इस खुजली की वजह से सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। नाक में एलर्जी किसी बाहरी चीज के सम्पर्क में आने से भी हो सकती है। नाक में खुजली होने के बहुत से कारण हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

- एलर्जिया के कारण नाक में एलर्जी हो सकती है।
- नेजल एलर्जी या एलर्जिक रायनाइटिस होना।
- अस्थमा होने पर नाक में एलर्जी हो सकती है।
- सिगरेट के धुएँ से भी नाक में खुजली होती है।
- नाक में धूल जाने के कारण खुजली हो सकती है।
- परप्युम के साइड इफेक्ट से भी नाक में खुजली होती है।
- जैनेटिक कारणों से भी नाक में खुजली महसूस हो सकती है।

घरेलू नुस्खे

नाक में हो रही खुजली को वेसे तो इंप्रून्टी विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के जरिये ठीक किया जा सकता है, लेकिन नाक की खुजली को आप घरेलू नुस्खों के जरिये भी सही कर सकते हैं। शहद और तुलसी- नाक में खुजली की वजह फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। संक्रमण दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते का पेस्ट बना लें। इसमें शहद मिलाएँ। इस पेस्ट को गुनगुने पानी के साथ लें। इस मिश्रण का सेवन करने से त्वचा में हो रही खुजली की समस्या भी दूर होती है। पपीता- पपीते का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। पपीते में ब्रोमलेन नाम का इंजाइम



आप चाहे मानसिक काम अधिक करते हैं या शारीरिक काम। यदि आपको काम करते समय बहुत जल्दी थकान होने लगती है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या है। जी हाँ, केवल पोषण की कमी के कारण ही नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी के कारण भी जल्दी थकान होती है। जो लोग नियमित रूप से जरूरी पानी नहीं पीते हैं, उन्हें काम करते समय अधिक थकान होना और अन्य लोगों की तुलना में जल्दी थकान होने जैसी समस्याएँ होती हैं। जानें, जल्दी थकान होने के अन्य कारण और उनके निवारण के तरीके

जल्दी थकने की वजह

- आमतौर पर जो लोग बहुत जल्दी थकान होने की समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके शरीर में कुछ खास तत्वों की कमी देखने को मिलती है।
- पानी की कमी
- खून की कमी
- विटामिन-बी12 की कमी
- फोलेट या फॉलिक एसिड की कमी

देखने को मिलती है। जल्दी थकान से बचने के तरीकों में ना केवल अपने खान-पान पर ध्यान देना है बल्कि यह भी ध्यान देना है कि जिस ड्रायट का सेवन आप कर रहे हैं और जिन ड्रिंक्स को आप ले रहे हैं, क्या वे आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यहां जानें कैसे रखा जाएगा इस बात का ध्यान।

तरल पदार्थों का सेवन

- जल्दी-जल्दी होने वाली थकान की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। इनमें जूस, सूप, छाछ, चाल इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही समय-समय सादा पानी पीते रहें। वयस्कों को हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए।

लगातार बनी रहती है थकान तो ऐसे रखें अपना ध्यान

तनाव को नियंत्रित करना सीखें

- जल्दी थकने की एक बड़ी वजह लगातार बना रहनेवाला तनाव भी होता है। तनाव का कारण चाहे जो भी लेकिन यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जल्द थका देता है। इसलिए तनाव से बचने के लिए हर दिन कुछ समय के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर करें। यह आपको मानसिक रूप से फिट रखने का काम करेगा।

फलियों का सेवन करें

- हरी फलियाँ कई तरह की वरायटी में आती हैं। खास बात यह है कि मौसम की प्रकृति और उस दौरान शरीर की जरूरत के अनुसार हर सीजन में अनेकाली फलियाँ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।
- हरी फलियाँ फाइबर युक्त होती हैं और इनका पाचन धीमी गति से होता है। इसलिए ये शरीर को लंबे समय तक

ऊर्जा देने का काम करती हैं, जिससे शरीर पर थकान कम हावी होती है।

ड्राईफ्रूट्स

- ऐसा नहीं है कि ड्राईफ्रूट्स का सेवन केवल सर्दियों में ही करना चाहिए। बल्कि सीमित मात्रा में और दूध के साथ ड्राईफ्रूट्स का सेवन गर्मियों में भी हर दिन किया जा सकता है।
- क्योंकि ड्राईफ्रूट्स केवल हमारे शरीर को गर्माहट देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि पोषण देने का काम भी करते हैं। शरीर की कमजोरी को दूर करने में भी यह अच्छी भूमिका निभाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में हम आपको मीट खाने की सलाह नहीं देना चाहते हैं। इस समय में आप थकान से बचने के लिए ड्राईफ्रूट्स यानी सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।



किसानों के चेहरों पर मोहन ने भावांतर योजना से लौटाई मुस्कान



हर्षवर्धन पान्डे

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादकों के लिए इस योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की है जो मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है। 2025 में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भावांतर योजना की घोषणा करके किसानों के हित में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस बड़ी घोषणा से राज्य के 50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन क्षेत्र और 25 लाख से अधिक छोटे-मझोले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

सोयाबीन मध्यप्रदेश के किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। यहां बाजार मूल्यों की अस्थिरता किसानों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान की है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई करेगी। यह योजना किसानों को बाजार जोखिम से बचाने का एक प्रभावी उपकरण साबित होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादकों के लिए इस योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की है जो मध्यप्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है। 2025 में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के बीच मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भावांतर योजना की घोषणा करके किसानों के हित में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस बड़ी घोषणा से राज्य के 50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन क्षेत्र और 25 लाख से अधिक छोटे-मझोले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिसूचित तिलहन फसल के लिए भावांतर योजना वर्ष 2018-19 से लागू की गई है। भारत सरकार ने घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा राज्य के मंडी के मांडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है। किसान पहले की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। एमएसपी और मंडी का मांडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का किसान को डीबीटी से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए किसान द्वारा ई-पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए किसान का उत्पादन मांडल भाव 4600 रूपए पर हुआ है तो समर्थन मूल्य 5328 में से शेष अर्थात भावांतर राशि 628 रूपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसान को समर्थन मूल्य बराबर ही राशि प्राप्त होगी। यदि किसान की उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है परंतु राज्य के औसत मांडल प्राइज के समतुल्य है ऐसी स्थिति में



भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। तीसरी स्थिति में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसत मांडल प्राइस से कम होने की दिशा में किसान को एमएसपी और घोषित औसत मांडल प्राइस के भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक स्थिति में किसान का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। मोहन सरकार के इस निर्णय से सोयाबीन उत्पादक के किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच के अंतर की राशि सरकार देगी। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का विक्रय किया जा सकेगा। राशि फसल विक्रय के 15 दिवस के अंतर किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मध्यप्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का विक्रय 24

अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। पंजीकृत कृषक और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से पूर्ण होगी। किसानों के भावांतर की राशि फसल विक्रय के 15 दिवस के भीतर उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसान मंडियों में पहले की तरह ही सोयाबीन का विक्रय करेंगे। यदि फसल एमएसपी से कम भाव पर बिकती है तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करेगी। इसके लिए किसानों को योजना में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। यदि मंडी में सोयाबीन का भाव एमएसपी से कम लेकिन राज्य सरकार के घोषित औसत मांडल भाव से अधिक है तो एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य का अंतर सरकार देगी। यदि मंडी भाव औसत मांडल भाव से भी कम है तो एमएसपी और मांडल भाव का अंतर किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा है कि योजना को पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए और किसानों तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव सरकार ने किसानों की समग्र कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में दशहरा के अवसर पर 8.84 लाख किसानों के खातों में 653.34 करोड़ रुपये की राहत राशि ट्रांसफर की गई जो अतिवृष्टि, बाढ़, कीट व्याधि और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से प्रभावित फसलों के लिए थी। इस बार प्रदेश के 13 जिलों के 4.94 लाख किसानों को पहली बार इस रोग के लिए विशेष सहायता मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के हित के लिए सरकार के पास राशि की कोई कमी नहीं है। किसान-कल्याण मोहन सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। जिस तरह धान और गेहूं पर किसानों को उनके परिश्रम की कीमत दिलवाने का काम किया गया उसी तरह प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी लाभ सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नजर आती है। मध्यप्रदेश की भावांतर योजना किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने का मोहन सरकार का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। इस योजना के माध्यम से सोयाबीन पर केंद्रित लाखों किसानों को एक तरफ जहाँ बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी वहीं इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए भावांतर योजना के प्रति किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। किसानों को अब किसी प्रकार का कोई नुकसान सरकार द्वारा नहीं होने दिया जायेगा। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु 5328 प्रति क्विंटल तय किया गया है लेकिन बाजार में कई बार किसानों को इससे कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही थी। ऐसे में मोहन सरकार की यह भावांतर योजना सोयाबीन किसानों की निश्चित तौर पर बड़ी राहत देने का काम करेगी। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

ट्रॉफी सिर्फ ढांचा नहीं टूर्नामेंट की आत्मा

गत दिनों एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक अवसर था। उपमहाद्वीप में जब-जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, तो इसे महज एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों के जन्मजात का संगम माना जाता है। ऐसे में उम्मीद थी कि यह फाइनल न केवल खेल कौशल का प्रदर्शन करेगा बल्कि खेलभावना की मिसाल भी पेश करेगा। मगर अफसोस कि मुकाबले के अंत में सबसे ज्यादा चर्चा खेल के नतीजे की नहीं, बल्कि ट्रॉफी वितरण के दौरान उपजे विवाद की रही। यह विवाद न केवल आयोगन समिति की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि खिलाड़ियों और क्रिकेट संस्थाओं की परिपक्वता पर भी। ट्रॉफी किसी भी टूर्नामेंट की आत्मा कही जा सकती है। यह केवल धातु का ढांचा नहीं, बल्कि उस महानत, संघर्ष और टीम भावना का प्रतीक है जिसके लिए खिलाड़ी महनों तक पसीना बहाते हैं। जब उसी ट्रॉफी को लेकर मंच पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यह दृश्य दर्शकों के मन में निराशा और खेल की गरिमा पर प्रश्नचिह्न छोड़ जाता है। एशिया कप जैसे भव्य टूर्नामेंट में यह और भी अस्वीकार्य है। जिस क्षण को उत्सव होना चाहिए था, वह असहमति और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। भारत-पाकिस्तान संबंधों का बोझ क्रिकेट हमेशा ढोता आया है। लेकिन खेल को हमेशा इन तनावों से ऊपर बताया गया है। यह मंच आपसी कटुता को पीछे छोड़कर सद्भाव और सम्मान का संदेश देने का अवसर देता है। किंतु जब ट्रॉफी वितरण जैसे अवसर पर भी शिष्टाचार और खेलभावना की कमी दिखे तो यह साफ संकेत है कि आयोगकों और खिलाड़ियों दोनों को आत्ममंथन की आवश्यकता है। यह केवल दो टीमों के बीच विवाद नहीं, बल्कि पूरे एशियाई क्रिकेट की रूढ़ि पर चोट है। इस घटना ने आयोगन समिति की तैयारी और निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की सफलता केवल मैदान पर खेले गए मैचों से नहीं, बल्कि उसके समान के सुचारु आयोजन से भी आंकी जाती है। यदि उस निर्णायक क्षण में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यह पूरे टूर्नामेंट की छवि धूमिल कर देता है। खिलाड़ियों के लिए भी यह क्षण आत्मचिंतन का है। वे केवल अपने खेल से ही नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। यदि मंच पर असहमति और विवाद दिखे तो इससे दर्शकों में गलत संदेश जाता है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, और उसकी गरिमा बनाए रखना हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है। ट्रॉफी जीतना निरसंह गौरव की बात है, किंतु खेल की मर्यादा बनाए रखना उससे कहीं बड़ा दायित्व है। यदि आयोगन समिति और खिलाड़ी इस घटना से सबक नहीं लेते तो भविष्य में ऐसे विवाद बार-बार क्रिकेट की छवि को आहत करेंगे। खेल को राजनीति और अहंकार से ऊपर रखना ही उसकी असली आत्मा है। स्पष्ट है कि एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी का विवाद एक शर्मनाक दृश्य था। इसने खेल के उस उज्वल क्षण को कलंकित कर दिया जिसे आने वाले वर्षों तक यादगार होना चाहिए था। अब यह क्रिकेट संस्थाओं और खिलाड़ियों पर है कि वे इस कलंक को धोकर खेल की गरिमा बहाल करें।

चिंतन-मनन

जीवन : परमात्मा का अनमोल उपहार

जीवन परमात्मा का अनमोल उपहार है। यह स्वयं ही इतना दिव्य, पवित्र और परिपूर्ण है कि संसार का कोई भी अभाव इसकी पूर्णता को खंडित करने में असमर्थ है। आवश्यकता यह है कि हम अपने मन की गहराई से अध्ययन कर उसे उत्कृष्टता की दिशा में उन्मुख करें। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ एवं अहम के दोषों से मन को विकृत करने के बजाए अपनी जीवनशैली को बदल कर सेवा, सहकार, सौहार्द जैसे गुणों के सहारे मानसिक रोगों से बचा जा सकता है और मानसिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन चार तरह की विशेषताएं लिए रहता है। इस संबंध में एक श्लोक प्रस्तुत है - बुद्धये फलं तत्त्व विचारणं/देहस्य सारं व्रतधारणं च/वित्तस्य सारं रिकलपाय दानं/वाचः फलं प्रतिकरणपारणाम। अर्थात्- बुद्धि का फल तभी सार्थक होगा, जब उसको पूर्ण विचार करके उस पर अमल करें। शरीर का सार सभी व्रतों की धारण करने से है। धन तभी सार्थक होगा, जब वह सुपात्र को दान के रूप में मिले और बात या वचन उसी से करें, जब व्यक्ति उस पर अमल करे। इसी का बेहतर तालमेल जीवन में बिटाना होता है। जो बिटा लेता है, वह भवभ्रमण से पार हो जाता है और जो नहीं बिटा पाता वह दुख में पड़ा गोता खाता रहता है। आप जब तक इस गहराई को नहीं समझेंगे, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि हम अपनी हर धड़कन की रफ्तार को समझें।



कालिताल माहोत

योगी आदित्यनाथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के तीन दिनों के भीतर एंटी रोमियो दस्ते के नाम से बनी पुलिस की छापामार टीमों सार्वजनिक स्थलों से लांपटो को खदेड़ने में जुटी थीं।जोकि आज दिन एंटी रोमियो स्व्वायड नारी शक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है।प्रदेश में महिलाओं और बेटियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है।महिलाओं और बेटियों को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के साथ सुरक्षा का माहौल उपलब्ध करने के लिए योगी की मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाने की शुरुआत की गई है।मुख्यमंत्री ने नगराज के पहले दिन मिशन शक्ति 5.0की शुरुआत की गई थी।योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी पुलिस ने पूरे यूपी में अभूतपूर्व अभियान चलाया,जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और जनसहभागिता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा रही है कि बचपन से लेकर जवानी तक हर लड़की की रखवाली राज्य के अधीन रहती है।कोई भी सरकार लक्ष्य से हट नहीं



रमेश सर्राफ धमोरा

पूरी दुनिया में 9 अक्तूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1874 में इसी दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 1969 में जापान के टाकियो शहर में आयोजित सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में इसी दिन को चयन किये जाने की घोषणा की गयी थी। एक जुलाई 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला भारत पहला एशियाई देश था। जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय मेल ट्रैफिक के आधार पर भारत शुरू से ही प्रथम श्रेणी का सदस्य रहा है। भारत में डाकघर का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से शुरू होता है जब रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 में पहली डाक व्यवस्था स्थापित की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कोलकाता में पहला डाकघर खोला और 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक राष्ट्रीय डाक सेवा की शुरुआत की। आज भारतीय डाक दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है जो बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाओं के साथ आम आदमी का भरोसेमंद साथी है। 1 अक्टूबर 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना के साथ ही भारत में पहली बार डाक टिकट भी जारी किया गया था। विश्व डाक दिवस का मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 15 से ज्यादा देशों में विविध तरीकों से विश्व डाक

योगी का एंटी रोमियो दस्ता महिला शक्ति का मजबूत पहरेदार

सकती इतरप्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी 1,500 थानों में गठित नए दस्ते की सनसनी फैला दी थी।शुरूआत के दौर में योगी की शक्ति से अभिन्न रोड रोमियो पुलिस की कार्यवाही को शक समझते थे।लेकिन धीरे धीरे एंटी रोमियो पर गिरफ्तार कसमें लगा और सुबे में गुंडागर्दी कम होने लगी।प्रदेश में उस दौर में सनसनी फैला दी,जैसे ऐसा लगता था कि कबूतरों के बीच बिल्ली को छोड़ दिया गया हो।एंटी रोमियो हवा की तरह आते है।अभी भी रोड रोमियो स्व्वायड से थर थर कांपते है।शुरू में करीब दो हजार नौजवानों को धर दबांचा।योगी ने उन रोमियो को पकड़ा,जिनके बाल लंबे,कुछ स्कूल और कॉलेज के पास पाए गए और कुछ यू ही भटक रहे थे।इनको घेर कर सरकार ने अच्छे संकल्प दिलवाया गया।कुछ मामलों में तो उठक बैठक करवाई गई। भारत दोहाद पर खड़ा है।एक तरफ यथास्थितिवादी ग्रामीण समाज और दूसरी तरफ शहरी समाज आधुनिकता, निजी प्रगति और नए तरह के सामाजिक रिश्तों की ओर कदम बढ़ा रहा है।व्हाट्टी फैशन और शरीर पर कम होती पोशाकों के जमाने का वास्तविकता को कोसो पीछे छोड़कर नए जमाने की दहलीज पर कदम रखने वाले युवक युवतियों को समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे पेश आए। देश में औरतों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में एक उत्तरप्रदेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था।वर्तमान में सुबे के काफी हालात सुधरे है।महिलाएं,बालिका कही पर आवागमन कर सकती है।वहां तक रात में भी किसी अकेली महिलायें और बेटियां सुरक्षित है।उत्तरप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में काफी कमी आई है।2017 का दौर भयंकर रहा है।2017

पहले महिलाओ और बच्चियों के साथ आए दिन अपहरण, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटना सामान्य बात थी।लेकिन वह भूतकाल की बात है।अपराध इतना बढ़ गया था कि महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं थीं।औरतों को चार दिवारी के भीतर अपराध का शिकार होना पड़ता था।यह बीते काल की बात है।लेकिन आज महिलाओं के साथ नहीं होता है।उत्तरप्रदेश के शक्त शासन के माध्यम से यूपी की कायापालट कर दी है।दहेज, धाव,सामुहिक बलात्कार,अगवा और फिरौती,यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं पूर्व सरकार में घटित होती थीं।योगी ने सर्वप्रथम एंटी रोमियो को ठीक करने के लिए सिर्फ छेड़छाड़ पर ही फोकस किया गया था।क्योंकि चारदिवारी के भीतर घरेलू हिंसा होती है। लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर बेहदगी तो चलन बन गया था।सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूपी पुलिस हर तरह की प्रवृति कर रही है। सड़कों पर रोमांस करने वाले पर चालान किये जा रहे है,जिससे उपरोक्त घटनाएं कम हो रही है।पुलिस रचनात्मक संदेश और अभियानों का उपयोग कर रही है।एनसीआरवी के अनुसार यूपी में साम्प्रदायिक हिंसा बिलकुल खत्म हो चुकी है।यूपी में अपराध एक चौथाई कम है।राज्य के हालात तेजी से सुधरे है।जिसमें राज्य सरकार की सख्ती का परिणाम है।।2023 में साम्प्रदायिक की घटना शून्य रही थी।यूपी में राष्ट्रीय औसत से 25 फीसद कम रही है।सड़कों पर शांति का आलम है।।2017 के बाद यूपी शांति और सद्भाव का गढ़ बन चुका है।लाव जिहाद के लड़ने और सरकार की सख्ती से काफी कम हुआ है।जबकि यूपी के हर कॉलेज में एंटी रोमियो दस्ता उपलब्ध कराया गया था।जिससे लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने में

सहूलियत रही है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले देश में 615 घटनाएं हुईं जिसकी तुलना में यूपी में मात्र 16 घटनाओं के साथ देश में 3.6वें स्थान पर है। डकेती (कड्ड 395) के मामलों में भारत में 3,792 (क्राइम रेट 0.3) के मुकाबले यूपी में 73 मामले दर्ज हुए, जो इसे नियर जीरो क्राइम रेट की श्रेणी में लाता है। बड़ी जनसंख्या के बावजूद यह कमी योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है। नवरात्र में शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान में योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्व्वायड ने सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर सतर्कता बढ़ाई।इस दौरान 10 लाख ,आठ हजार से उपर मंदिरों की गहन जांच करवाई गई।जिसमें संधिध गतिविधियों पर पैनी रखी गई। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही की गई।संधिध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।जिसमें 3,972 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।धार्मिक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंग से पूर्ण हुआ।सड़क पर छेड़छाड़ में देश में यूपी ही अग्रणी राज्य है यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।लेकिन देश में हर राज्य में छेड़छाड़ की घटना बरती ही है।पुलिस ऐसे मामले शॉर्टआउट की भी करती है।सड़क पर लड़किया देखकर सिटी बजाना,पुकारना,छेड़ना,यौन उत्पीड़न और गाली गलौज देश में हर राज्य की समस्या है।लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा था।क्योंकि योगी के पूर्ववर्ती सरकार इस पर कड़क कार्यवाही नहीं करती थी।यही बड़ा कारण था देश में हर राज्य सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के अनूठे तरीके ईजाद करने में लगी है जो इतने दमनकारी भी नहीं है।

विश्व डाक दिवस: समय के साथ बदल रहा है डाक विभाग

दिवस आयोजित किया जाता है। भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है। वह लंबे सफर की देन है। अग्रजों ने डेढ़ सौ साल पहले अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की पहल की थी। उन्होंने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अग्रजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर ही केंद्रित थी। हमारे देश में पहले डाक विभाग का इतना अधिक महत्व था कि फिल्में तक में डाकिये पर कई मशहूर गाने फिल्माये गये हैं। मगर अब नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव ने डाक विभाग के महत्व को बहुत कम कर दिया है। आज लोगों में हाथों से चिट्ठियां लिखना छोड़ दिया है। अब ई-मेल, वाट्सएप व सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यमों से मिन्नटों में लोगों में संदेशों का आदान प्रदान हो जाता है। आज डाक में लोगों की चिट्ठियां तो गिनती की ही आती है। मनीआर्डर भी बन्द से ही हो गये हैं। मगर डाक से अन्य सरकारी विभागों से सम्बन्धित कागजात, बैंकों व अन्य संस्थानों के प्रपत्र काफी संख्या में आने से डाक विभाग का महत्व फिर से एक बार बढ़ गया है। डाक विभाग कई दशकों तक देश के अंदर ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश तक सूचना पहुंचाने का सर्वाधिक विश्ववर्नीय, सुगम और सस्ता साधन रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों के बढ़ते दबदबे और फिर सूचना तकनीक के नये माध्यमों के प्रसार के कारण डाक विभाग की भूमिका लगातार कम होती गयी है। वैसे इसकी प्रासंगिकता पूरी दुनिया में आज भी बरकरार है। भारत में डाक विभाग के महत्व को मशहूर शायर निदा फाजली के शेर सीधा-साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान से समझा जा सकता है। शायर निदा फाजली ने जब यह शेर लिखा था उस वक्त देश में संदेश पहुंचाने का डाक विभाग ही एकमात्र साधन था। डाकिये के थैले में से निकलने वाली चिट्ठी पढ़कर कोई खुश होता था तो कोई दुखी। कुछ वर्ष पूर्व तक डाक विभाग हमारे जनजीवन में

एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। गांव में जब डाकिया आता था तो बच्चे-बूढ़े सभी उसके साथ डाक घर की तरफ इस उत्सुकता से चल पड़ते थे कि उनके भी किसी परिजन की चिट्ठी आयेगी। डाकिया जब नाम लेकर एक-एक चिट्ठी बांटना शुरू करता तो सभी लोग अपनी या अपने पड़ोसी की चिट्ठी ले लेते व उसके घर जाकर उस चिट्ठी को बड़े चाव से देते थे। उस वक्त शिक्षा का प्रसार ना होने से अक्सर महिलायें अनपढ़ होती थीं। इसलिये चिट्ठी लाने वालों से ही चिट्ठियां पढ़वाती थीं और लिखवाती भी थीं। कई बार चिट्ठी पढ़ने-लिखने वाले बच्चों को ईनाम स्वरूप कुछ पैसा या खाने को गुड़, पताशे भी मिल जाया करते थे। इसी लालच में बच्चे ज्यादा से ज्यादा घरों में चिट्ठियां पहुंचाने का प्रयास करते थे। उस वक्त गांवों में बैंक शाखा भी नहीं होती थी। इस कारण बाहर कमाने वैसे लोग अपने घर पैसा भी डाक में मनीआर्डर के द्वारा ही भेजते थे। मनीआर्डर देने डाकिया स्वयं प्राप्तकर्ता के घर जाता था व भुगतान के वक्त एक गवाह के भी हस्ताक्षर करवाता था। डाक विभाग अति आवश्यक संदेश को तार के माध्यम से भेजता था। तार की दर अधिक होने से उसमें संक्षिप्त व जरूरी बातें ही लिखी जाती थीं। तार भी साधारण जरूरी होते थे। जरूरी तार की दर सामान्य से दुगुनी होती थी। देश में पहली बार 11 फरवरी 1855 को डाक शुरू हुई तार सेवा को सरकार ने 15 जुलाई 2013 से बन्द कर दिया है। इसके साथ ही डाक विभाग ने रिजिस्टर्ड डाक सेवा को भी एक अक्तूबर 2025 से स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया है। भारतीय डाक विभाग पिनकोड नम्बर (पोस्टल इंडेक्स नम्बर) के आधार पर देश में डाक वितरण का कार्य करता है। पिनकोड नम्बर का प्रारम्भ 15 अगस्त 1972 को किया गया था। इसके अन्तर्गत डाक विभाग द्वारा देश को नौ भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। संख्या 1 से 8 तक भौगोलिक क्षेत्र हैं व संख्या 9 सेना की डाक सेवा को आवंटित किया गया है। पिन कोड की पहली संख्या क्षेत्र दूसरी संख्या उपक्षेत्र, तीसरी संख्या जिले को दर्शाती है। अन्तिम तीन संख्या उस जिले के विशिष्ट डाकघर को दर्शाती है।

डाक विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) शुरू किया है। देश के हर व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के क्रम में यह एक बड़ा विकल्प होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर में बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में इस के माध्यम से देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क अस्तित्व में आएगा। जिसकी हर गांव तक मौजूदगी होगी। इन सेवाओं के लिए पोस्ट विभाग के 11000 कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं देंगे। बदलते हुए तकनीकी दौर में दुनिया भर की डाक व्यवस्थाओं ने मौजूदा सेवाओं में सुधार करते हुए डाक को नयी तकनीकी सेवाओं के साथ जोड़ा है। डाक, पार्सल, पत्रों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की हैं। डाक घरों द्वारा मुहैया करायी जानेवाली वित्तीय सेवाओं को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। दुनियाभर में इस समय 55 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार की पोस्टल ई-सेवाएं उपलब्ध हैं। भविष्य में पोस्टल ई-सेवाओं की संख्या और अधिक बढ़ायी जायेगी। डाक विभाग से 82 फीसदी वैश्विक आवादी को होम डिलीवरी का फायदा मिलता है। भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रख कर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ था। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। जिससे इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आज भी आम आदमी डाकघरों और डाकिये पर भरोसा करता है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में आम जनता का इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है। इसके पीछे डाक विभाग के कार्यों का बरसों का श्रम और लगातार प्रदान की जा रही सेवा छिपी है। (लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)



भागवत के किरदार में आई चुनौतियों पर बोले जितेंद्र कुमार

अभिनेता जितेंद्र कुमार इन दिनों वे अपनी आगामी फिल्म भागवत सेक्टर 1- राक्षस को लेकर चर्चा में हैं। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जितेंद्र इस फिल्म में नेगेटिव रोल अदा करते दिखेंगे। फिल्म भागवत में जितेंद्र कुमार को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जाएगा। फिल्म की रिलीज से पहले जितेंद्र कुमार ने एक बिल्कुल अलग किरदार में अपनी दिलचस्पी को लेकर बात की। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जितेंद्र ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, यह एक हैरान कर देने वाली फिल्म है और इसे आश्चर्यजनक तरीके से बनाया गया है। हम ट्रेलर को मिली प्रतिक्रियाओं से काफी खुश हैं।

किरदार के लिए लेखक और निर्देशक से की लंबी बात

जितेंद्र ने अपने किरदार को लेकर कहा कि उन्होंने इस भूमिका में ढलने के लिए लेखकों और निर्देशक के साथ व्यापक चर्चा की थी। जितेंद्र ने कहा, यह सुनिश्चित किया गया कि किरदार में रियलिज्म बरकरार रहे और मेरे किरदार की अलग-अलग परतों में भी यह हकीकत नजर आए। सभी सीन असली रियल लोकेशन पर फिल्माए गए, लेकिन मुझे कहानी की पृष्ठभूमि में गहराई से न जाने के लिए कहा गया, क्योंकि कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है। उन्हें लगा कि यह गलत दिशा में जा सकती है।

किरदार का हर हिस्सा अलग है

जितेंद्र ने अपने किरदार को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने आगे कहा, इस भूमिका का हर हिस्सा एक अलग रंग और परत लेकर आता है। कुछ ऐसा, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। जितेंद्र ने बताया कि शूटिंग के दौरान खासकर एक सीन पूरा करने के बाद वह उत्साहित और घबराए हुए दोनों थे। उन्होंने आगे कहा, जब भी हम कोई नया सीक्वेंस शूट करते थे तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत उत्सुक रहता था। हर सीन मुझे घबराहट से भर देता था। मैं सोचता था कि मुझे इसे जल्दी से करना है और फिर देखना है कि यह कैसा बना है। मुझे आगे क्या बदलाव करने की जरूरत है?



लापता लेडीज से मिली पहचान

किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज में निताशी गोयल की एक्टिंग को खूब सराहा गया था। उनके साथ इस फिल्म में प्रतिभा रांटा और स्पर्शा श्रीवास्तव भी मुख्य भूमिकाओं में थे। साधारण लड़की के किरदार को उन्होंने जिस गहराई और मासूमियत से निभाया, उसने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। इसी फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री का उभरता सितारा बना दिया।

आनंद देवरकोंडा के भाई संग पर्दे पर रोमांस करेंगी निताशी गोयल

फिल्म लापता लेडीज से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री निताशी गोयल अब एक बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं। फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक निताशी जल्द ही तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय चेहरे आनंद देवरकोंडा के साथ अपनी पहली पेन-इंडिया फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। लंबे समय से निताशी के फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और अब इस खबर के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है।

पेन-इंडिया फिल्म की शुरुआत

अब खबर है कि निताशी, आनंद देवरकोंडा के साथ एक पेन-इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। इस फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है और शूटिंग अगले महीने शुरू होगी। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 2025 की सबसे बड़ी क्रॉस-इंडस्ट्री फिल्मों में से एक होगा, जिसमें हिंदी और साउथ सिनेमा की लोकप्रियता को जोड़कर नए दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि फिलहाल मेकर्स की ओर से इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। खबरें हैं कि फिल्म के मेकर्स ने इसे बड़े पैमाने पर बनाने का प्लान तैयार किया है। भव्य सेट, दमदार म्यूजिक और स्टाइलिश विजुअल्स के साथ यह फिल्म दर्शकों को नया अनुभव देने वाली



है। हालांकि कहानी अभी तक गुप्त रखी गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह एक एनर्जेटिक एंटरटेनर होगी, जो हर उम्र के दर्शकों को आकर्षित करेगी।

निताशी का बढ़ता सफर

सिर्फ यही नहीं, निताशी को एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है। खबरों के अनुसार, वह अभय वर्मा के साथ रत्ना सिन्हा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में भी नजर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि यह फिल्म शादी में जरूर आना के सीक्वल के तौर पर तैयार की जा रही है।

कान रेड कार्पेट पर भी छाई

निताशी ने हाल ही में कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। वहां उन्होंने अपने लुक से पुराने दौर की दिग्गज अभिनेत्रियों- रेखा, मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस और श्रीदेवी को ट्रिब्यूट दिया। उनके इस अंदाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें लाइमलाइट में ला दिया।

भाई टोनी के साथ नया गाना कोका कोला-2 लेकर आ रही हैं नेहा कक्कड़

मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ फैंस के लिए तोहफा लेकर आ रहे हैं। नेहा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि वह कोका-कोला गाने का नया वर्जन लेकर आ रही हैं। नेहा कक्कड़ ने फैंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्ट साझा किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कोका कोला-2 जल्द ही आने वाला है। तस्वीरों में नेहा भाई टोनी और जुनियर के साथ नजर आ रही हैं। नेहा एक शानदार लज्जरी कार पर स्टाइलिश पोज दे रही हैं, जबकि उनके दोनों तरफ भाई टोनी कक्कड़ और छोटा जुनियर खड़े हैं। नेहा ने कैप्शन में लिखा, कोका कोला-2 जल्द ही आने वाला है। यह पोस्ट देख फैंस गाने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस नए वर्जन में टोनी कक्कड़ ने कम्पोजिंग, प्रोडक्शन और लिट्रिक्स का जिम्मा संभाला है। फैंस को

उम्मीद है कि उनका क्रिएटिव टच हमेशा की तरह इस बार भी धमाकेदार रहेगा। डायरेक्शन का दमदार काम इनफिल्टर ने संभाला है। बता दें, 'सॉन्ग कोका-कोला' पहले टोनी कक्कड़ ने रैपर यंग देसी के साथ मिलकर बनाया था, जिसके बाद यह काफी वायरल हुआ था। इसके बाद इसे 2019 में फिल्म लुका-छुपी में नए वर्जन में रिलीज किया गया था। गाने को नेहा और टोनी कक्कड़ ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। इसके लिट्रिक्स टोनी और मैलो-डी ने मिलकर लिखे थे। वहीं टोनी ने संगीतबद्ध भी किया था। रैपिंग का काम यंग देसी ने किया था। अब यह गाना फैंस की उम्मीदों को पूरा करने को बेताब है।



रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की सगाई!

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के अफेयर की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। कथित तौर पर एक निजी समारोह में इन दोनों ने सगाई कर ली है। अगले साल फरवरी में इनके घर शहनाई बज सकती है।

निजी समारोह में हुई सगाई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों की सगाई एक प्राइवेट सेरेमनी में परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के बीच हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ने अपनी शादी का एलान करने से पहले कुछ दिनों इंतजार करने का फैसला लिया है। इसलिए सगाई को लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

रश्मिका के हालिया पोस्ट ने दी अफवाहों को हवा

रश्मिका मंदाना और विजय की सगाई की रुमर्स दरअसल, रश्मिका के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुईं। रश्मिका ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं, जिनमें वे साड़ी में नजर आ रही हैं। यह दृश्यों के अवसर की तस्वीरें हैं। रश्मिका ने इन्हें साझा कर फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं और थामा के टैलर को अच्छे रेसॉयन्स मिलने पर शुक्रिया कहा है। मगर, नेटिजन्स ऐसे कयास लगा रहे हैं कि रश्मिका की यह फोटोज विजय के घर की हैं और दोनों की सगाई हो गई है। हालांकि, सगाई की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। न ही कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है।



पहले भी आती रही हैं ऐसी खबरें

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी और सगाई से जुड़ी खबरें पहले भी आती रही हैं। कल रश्मिका मंदाना की आगामी फिल्म द गर्लफ्रेंड पर एक बड़ा एलान होने वाला है। ऐसे में दावे यह भी किए जा रहे हैं कि कहीं इसी सिलसिले में यह कोई पीआर स्टंट तो नहीं है। अब विजय और रश्मिका ने वाकई सगाई कर ली है या नहीं, यह तभी स्पष्ट हो पाएगा, जब दोनों की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी।



काम के घंटे को लेकर रानी मुखर्जी ने किया रिप्लेट

बीते कुछ वक्त से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर बहस चल रही है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे काम करने की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने सदीप रेड्डी वांगा की आगामी फिल्म 'सिपरिट' को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गरम हो गया था। इसपर कई सेलेब्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। अब काम के घंटों को लेकर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी रिप्लेट किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशन में अपने करियर को लेकर भी बात कही है।

शूटिंग के दौरान भी कैसी रखती थी बच्चे का ख्याल?

एएनआई से बात करते हुए रानी मुखर्जी ने फिल्म हिचकी की शूटिंग के दिनों को याद किया और अपनी बेटी आदिरा के पालन-पोषण के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'जब मैंने हिचकी की थी, तब आदिरा 14 महीने की थी। मुझे सबकुछ करके शहर के एक कॉलेज में शूटिंग करने जाना होता था।'

काम के बीच में जिम्मेदारियों को भी बैलेंस किया

आगे उन्होंने फिल्म की शूटिंग और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच में बैलेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जुहू स्थित मेरे घर से शूटिंग की जगह तक पहुंचने में लगभग दो घंटे लगते थे और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहता था। इसलिए मैंने तय किया था कि बेटी के लिए सबकुछ करके 6.30 बजे निकल जाती और शूटिंग शुरू कर देती। मेरा

पहला शॉट सुबह 8 बजे होता था और मैं 12.30 से 01 बजे तक सब कुछ निपटा लेती थी। मेरे वरु मेम्बर्स बहुत योनाबाद थे, जिस वजह से उन 6-7 घंटों में मैं अपनी शूटिंग पूरी कर लेती थी। शहर में ट्रैफिक शुरू होने से पहले, मैं 3 बजे तक घर पहुंच जाती थी। मैंने अपनी फिल्म इसी तरह की।'

काम के घंटे आपसी समझ पर आधारित हैं

काम के घंटों को लेकर रानी मुखर्जी ने कहा, 'आजकल ये बातें चर्चा में हैं क्योंकि शायद

लोग बाहर इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह सभी कार्यों का एक सामान्य नियम रहा है। मैंने भी ऐसा किया है, जहां मैंने कुछ घंटों तक काम किया है। अगर निर्माता को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप फिल्म नहीं करते। इसलिए यह भी एक विकल्प है। कोई किसी पर कुछ भी थोप नहीं रहा है।'

रानी मुखर्जी का वर्कफंट

रानी मुखर्जी के काम की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार मिसेज चटर्जी वर्सेज नावें में देखा गया था। वहीं उनकी आगामी फिल्म मर्दानी 3 है।

बताया कब करेंगी निर्देशन

अभिनेत्री से उनकी निर्देशन को लेकर रुचि के बारे में सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं कि मैं इस पेशे में हमेशा कहती हूँ कि कभी ना मत कहो। मुझे लगता है कि मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मुझे पता होता है कि मैं कब निर्देशन के लिए तैयार हूँ या मुझे पता होता है कि वह समय कब आएगा। अभी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अभी, मैं एक अभिनेत्री होने और निर्देशन होने से बहुत खुश हूँ।'

संक्षिप्त समाचार

ट्रम्प ने अमेरिका में आने वाले ट्रकों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को मीडियम और हवी ट्रकों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये 1 नवंबर से लागू होगा। पहले यह शुल्क 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे एक महीने टाल दिया गया है। ट्रम्प ने अपने दृष्ट सोशल अकाउंट पर लिखा, 1 नवंबर 2025 से, दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सभी मध्यम और भारी वाहन ट्रकों पर 25% शुल्क लगेगा। अमेरिका में ज्यादातर ट्रक पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको से आते हैं, जहां पहले से ही व्यापार समझौता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार, पिछले साल अमेरिका ने 2 लाख 45 हजार 764 मध्यम और भारी वाहन ट्रक खरीदे, जिनमें से अधिकांश कनाडा और मेक्सिको से आए। इनकी कुल कीमत 201 अरब डॉलर रही, जिसमें कनाडा से 45 अरब और मेक्सिको से 156 अरब डॉलर का योगदान था। अमेरिकी ऑटोमोबाइल बाजार में ये ट्रक कुल वाहनों के सिर्फ 5% हिस्से के हैं। लेकिन एसाइंडपी ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी अमेरिका में इनकी मांग का लगभग 80% अमेरिका ही पूरा करता है। इन ट्रकों को वजन के आधार पर बांटा जाता है। मध्यम ट्रक का वजन 14,000 से 33,000 पाउंड के बीच होता है, जबकि 33,000 पाउंड से ज्यादा वजन वाले को भारी ट्रक कहा जाता है। अमेरिका में ये मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स (माल ढुआई), निर्माण कार्य और कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं।

सीडीएस ने सभी के लिए कोविड-19 टीके की सिफारिश बंद की

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग की शीर्ष इकाई- सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीडीसी) ने अब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अपनी सिफारिशें बदल दी हैं। सीडीसी ने कहा कि अब किसी भी आयु वर्ग के शख्स के लिए टीका अनिवार्य नहीं है। सीडीसी अब सभी लोगों को टीके लगवाने की सिफारिश नहीं कर रही है। यह फैसला स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर की तरफ से नियुक्त नए सलाहकार समूह की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इससे पहले 6 महीने और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वार्षिक बूस्टर डोज की सिफारिश की जाती थी, लेकिन अब यह निर्णय मरीजों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। केनेडी ने मई में स्वास्थ्य बच्चों और नाभवती महिलाओं के लिए वैक्सीन की सिफारिश हटाने की घोषणा की थी। उन्होंने सीडीसी की पारंपरिक सलाहकार समिति को हटाकर नया समूह बनाया। नए समूह में पिछले महीने हुए मतदान के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी अमेरिकी टीके को लेकर स्वयं निर्णय लें। सीडीसी ने यह भी कहा है कि बुजुर्गों को डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा, सीडीसी ने चिकित्सकों (फिरसेला) की पहली सुरक्षा को अलग से देने की सिफारिश की है। सीडीसी का कहना है कि संयुक्त टीके से बुखार और दौरे का खतरा अधिक होता है।

यूनेस्को ने मिस्र के व्यक्ति को नया निदेशक बनाया, अमेरिका के हटने के बाद बदलाव

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई-यूनेस्को को पहली बार अरब देशों से जुड़ा महानिदेशक मिल सकता है। मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री खालिद एल-अनानी को एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने निदेशक पद के लिए नामित किया है। अगले महीने उज्बेकिस्तान में यूनेस्को की महासभा होने वाली है। यदि इसमें खालिद एल-अनानी के निदेशक बनने की पुष्टि हो जाती है, तो वे एजेंसी की कमान संभालेंगे। हाल ही में अमेरिका के यूनेस्को से बाहर होने के फैसले के बाद यह बदलाव हो रहा है। ये संस्था बजट संकट का सामना भी कर रही है। नॉमिनेशन के समय एल-अनानी ने कांगो के अर्थशास्त्री फिमिन एडुआर्ड मातोको को पीछे छोड़ा। मातोको शरणार्थी शिविरों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि यूनेस्को विपक्ष धरोहर स्थलों की सुरक्षा के अलावा, लड़कियों की शिक्षा, होलोकोस्ट (यहूदियों के नरसंहार) को लेकर जागरूकता और विकासशील देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे अहम कार्यों के लिए जाना जाता है।

हिजबुल्लाह कब छोड़ेगा हथियार? निरस्त्रीकरण के सवाल पर लेबनानी सेना प्रमुख ने सरकार को दी जानकारी

बेरुत, एजेंसी। लेबनान के सेना प्रमुख जनरल रुडोल्फ हेकाल ने पहली बार सरकार को ये जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह हथियार कब छोड़ेगा। निरस्त्रीकरण की योजना एक महीने पहले कैबिनेट में चर्चा के बाद सामने आई थी। इसमें सभी हथियारों को सरकार के नियंत्रण में लाने की बात कही गई थी। हालांकि, इस योजना का विवरण गोपनीय रखा गया है। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस योजना को खारिज कर दिया है।

टेक्सास में गैस स्टेशन पर भारतीय छात्र की हत्या करने वाला गिरफ्तार

ह्यूस्टन, एजेंसी। अमेरिका के टेक्सास राज्य में 23 वर्षीय एक युवक को भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शुक्रवार रात फोर्ट वर्थ शहर के एक गैस स्टेशन पर हुई, आरोपी की पहचान रिचर्ड फ्लोरेज नॉथ रिचलैंड हिल्स के निवासी रूप में हुई है। आरोपी ने दूसरी जगह पर भी चलाई गोलियां: इसके कुछ ही समय बाद, आरोपी ने करीब एक मील दूर एक अन्य वाहन पर भी गोलियां चलाईं, लेकिन वहां कोई घायल नहीं हुआ। बाद में उसने पास के एक घर में घुसने की कोशिश करते हुए अपनी कार गेट से टकरा दी। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। फोर्ट वर्थ पुलिस प्रवक्ता ऑफिसर ब्रैड पेंजे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की गाड़ी से एक बंदूक बरामद की है। आरोपी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि फोर्ट वर्थ और टैरेंट काउंटी की ओर से इस मामले में औपचारिक बयान और आगे की जांच रिपोर्ट सरकारी शटडाउन के कारण कुछ देर से जारी की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हुआ है।

वादत से परिवार और समुदाय में शोक: भारतीय छात्र की हत्या के मामले में ह्यूस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वे चंद्रशेखर के



परिवार से संपर्क में हैं और उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। वहीं स्थानीय भारतीय-अमेरिकी समुदाय और विदेशी छात्र इस घटना से बेहद दुखी और भयभीत हैं। उनका कहना है कि हाल के महीनों में भारतीय छात्रों पर बढ़ते हमलों और रहस्यमय मौतों ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। चंद्रशेखर पोल के परिवार और मित्रों की मदद के लिए एक गॉफंडमी अभियान शुरू किया गया है, जिससे उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने और परिवार को आर्थिक सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रशेखर पोल तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे। उन्होंने बैचलर ऑफ इंटरल सजरी (बीडीएस) की पढ़ाई भारत में पूरी की थी और दो साल पहले अमेरिका गए थे ताकि वे डेटा

एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री कर सकें। वे नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी, डेंटन से छह महीने पहले ही एमएस पूरा कर चुके थे और नौकरी की तलाश में थे। उनके भाई दामोदर पोल ने बताया कि वह आत्मनिर्भर बने रहने के लिए पार्ट-टाइम गैस स्टेशन में काम कर रहे थे। अमेरिका में बढ़ती घटनाएं, गहराता डर अमेरिका में इस तरह वे कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी 2025 में, कनेक्टिकट में तेलंगाना के 26 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं रॉपर्टुडो लिले के एक युवक को भी अमेरिका में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। सितंबर 2025 में, महबूबनगर जिले के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को कैलिफोर्निया में पुलिस ने गोली मार दी थी, जब उसका अपने

रूममेट से झगड़ा हुआ था। इन मामलों के बाद, भारतीय दूतावासों को बार-बार छात्रों और उनके परिवारों की सहायता के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है। शवों को भारत लाने में कई बार हफ्तों लगा जाते हैं, क्योंकि प्रक्रिया में कानूनी और प्रशासनिक जटिलताएं शामिल होती हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल इस वारदात के बाद फिर से विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, देर रात या असुरक्षित इलाकों में काम करना कई बार उन्हें खरबे में डाल देता है। भारतीय समुदाय के लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय और स्थानीय प्रशासन ऐसे छात्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करें और देर रात काम करने वालों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराएं।

ब्राजील के राष्ट्रपति सिलवा के बदले सुर, टैरिफ कम करने के लिए 30 मिनट तक ट्रंप से की बातचीत

ब्रासीलिया, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति दुनियाभर के कई देशों पर भारी पड़ रहा है। इसमें भारत, ब्राजील जैसे देशों का नाम भी शामिल है। इसी बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिलवा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ब्राजीलियाई वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैरिफ और स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों को हटाने का अनुरोध किया है। दोनों नेताओं ने इस मामले में कुल 30 मिनट तक फोन पर आपस में बातचीत की।

इस दौरान ट्रंप ने कहा कि लूला के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत रही। दोनों ने मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था और व्यापार पर चर्चा की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हम आगे भी चर्चा करेंगे और निकट भविष्य में ब्राजील और अमेरिका में मिलेंगे।

मैंने जो कहा, वह बहुत असरदार था, वे रुक गए, ट्रंप ने फिर किया भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मई में चले संघर्ष को रुकवाने का दावा किया है। इतना ही नहीं ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ को हथियार बनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को रोकने में टैरिफ (आयात शुल्क) का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया। जो उन्होंने कहा था, वह बहुत असरदार साबित हुआ। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, टैरिफ अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम टैरिफ की वजह से शांति-रक्षक हैं। हम सैकड़ों अरब डॉलर कमाते हैं, लेकिन साथ ही टैरिफ के कारण हम युद्ध रोकने की ताकत भी रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने टैरिफ की ताकत का

इस्तेमाल न किया होता, तो आज भी चार युद्ध चल रहे होते। ट्रंप ने कहा, मैं युद्ध रोकने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे एक-दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे। सात विमान गिराए गए थे। वे लड़ाई के लिए तैयार थे। दोनों ही परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता कि मैंने क्या कहा था, लेकिन जो मैंने कहा वह बहुत प्रभावी था। वे रुक भी गए। यह टैरिफ और व्यापार पर आधारित था।

भारत करता रहा है तीसरे पक्ष के दुखल से इनकार गौरतलब है कि भारत ने पहलागाम हमले के साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी डॉकों को निशाना बनाया गया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलागाम में हुए हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। चार दिन तक चले हमलों के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ था। तब ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए संघर्ष रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश की थी। हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता दोनों सेनाओं के डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) के बीच प्रत्यक्ष बातचीत से हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। ट्रंप लगातार करते रहे हैं सात युद्ध रुकवाने का दावा उधर ट्रंप ने लगातार दावा किया कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक सात युद्ध खत्म करवाए हैं। इसमें भारत-पाकिस्तान, कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, कॉन्गो-रवांडा, इराक-इरान, मिश्र-इथियोपिया और आर्मेनिया-अजर्बैजान के बीच संघर्ष शामिल हैं। ट्रंप कहते रहे हैं कि इनमें से कम से कम आधे युद्ध भेरे व्यापारिक कौशल और टैरिफ की ताकत से खत्म हुए। अगर भेरे पास टैरिफ न होते, तो आज भी चार युद्ध चल रहे होते और रोज हजारों लोग मारे जा रहे होते।

कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप; जापान की भावी पीएम ताकाइची को दी बधाई

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते दो बड़े अंतरराष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने जापान की भावी प्रधानमंत्री साने ताकाइची को उनकी जीत पर बधाई दी है।

स्टब हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने सोमवार को बताया कि ट्रंप मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से व्हाइट हाउस में औपचारिक बैठक करेंगे। इसके बाद गुरुवार को वे अपने आठवें कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसी दिन दोपहर को उनकी फिनलैंड के

जवाब दिया, रियल एस्टेट की तरह कुछ जगहों बिकाऊ नहीं होती। कनाडा भी बिकाऊ नहीं है, और कभी नहीं होगा। इस पर भी ट्रंप ने अपनी बात से पीछे नहीं हटते हुए कहा, समय बताएगा। मैं कभी नहीं पर विश्वास नहीं करता। कई बार जो चीजें नामुमकिन लगती हैं, वे दोस्ताना तरीके से मुमकिन हो जाती हैं। जापान की नई महिला प्रधानमंत्री को दी बधाई: उन्होंने बताया कि ट्रंप ने जापान की नई नेता साने ताकाइची को भी बधाई दी है। लेविट ने बताया कि, राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे कहा है कि मैं जापान को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। वह

एक बेहद सम्मानित और समझदार नेता हैं, जो हमारे महान सहयोगी देश जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। जापान में इतिहास रचने जा रही साने ताकाइची: ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जापान की भावी प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बुद्धिमान और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला बताया। उन्होंने कहा कि वे जापान के अद्भुत लोगों को भी बधाई देते हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ताकाइची के चुन जाने के बाद वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, जो देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से हमारे संबंध खराब होंगे

मास्को, एजेंसी। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगाह करने के अंदाज में उनके रूसी समकक्ष पुतिन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दीं तो द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। पुतिन ने कहा, यूक्रेनी सेना इन मिसाइलों को खुद नहीं चला पाएगी। उन्होंने अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर मद्दद करने का दावा करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। वैश्विक ताकतों के टकराव और लंबे समय से जारी संघर्षों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति की तो वाशिंगटन और मास्को के बीच संबंधों खराब हो जाएंगे। एक मिसाइल की कीमत 11.44 करोड़ रुपये: सितंबर के अंत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि व्हाइट हाउस कीव को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा। एक मिसाइल की कीमत 11.44 करोड़ रुपये है। इनकी मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है, जिससे ये मिसाइलें मास्को और उसके बाहर भी हमला कर सकेंगी। अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर यूक्रेन के साथ प्रत्यक्ष भागीदारी के आरोप पुतिन ने शनिवार को एक



पाकिस्तान ने अमेरिका को खनिजों की पहली खेप भेजी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की छोटी खेप भेजी है। ये खनिज पिछले महीने अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटिजिक मेटल्स (यूएसएसएम) के साथ हुए 50 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत भेजे गए। हालांकि इन्हें भेजने की टाइमिंग नहीं पता चल पाई है। इस सौदे के अंतर्गत पाकिस्तान में खनिजों की खोज और प्रोसेसिंग के लिए कारखाने बनाना है। ये नमूने पाकिस्तानी सेना की ब्रांच फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन की मदद से तैयार किए गए। यूएसएसएम ने इसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच दोस्ती का बड़ा कदम बताया। कंपनी का कहना है कि यह समझौता खनिजों की खोज से लेकर प्रोसेसिंग तक सब कुछ कवर करता है। इमरान खान की पार्टी ने सौदे का विरोध किया: वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसका विरोध किया है। पीटीआई नेता शेख वक्कास

कहा कि संसद और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। हम देश के हितों के खिलाफ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूएसएसएम डिफेंस से जुड़े खनिज रिसाइकल करती है: यूएसएसएम कंपनी का कहना है कि यह सौदा खनिजों की खोज से लेकर रिसाइकल बनाने तक सब कुछ कवर करता है। मिसूरी की यह कंपनी ऐसे खनिज बनाती और रिसाइकल करती है जो रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के लिए जरूरी हैं। खेप में एंटीमनी, कॉपर कंसप्ट्रेट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडिमियम व प्रोजियोडिमियम शामिल हैं। इससे पहले सितंबर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान मुनीर ने ट्रंप को रेयल मिनरल्स से भरा ब्रीफकेस दिखाया था। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास 6 ट्रिलियन डॉलर की खनिज

संपदा है। वो चाहता है कि अमेरिकी निवेशक यहां इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान का अमेरिका को बलूचिस्तान में पोर्ट बनाना का प्रस्ताव पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने तीन दिन पहले ही अमेरिका से बलूचिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव शेर्य किया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिकी निवेशक बलूचिस्तान के पसनी शहर में अरब सागर के किनारे एक नया पोर्ट डेवलप करके चलाएं। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि यह बंदरगाह सिर्फ व्यापार और खनिजों के लिए है। अमेरिका को यहां सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं होगी। पासनी, ग्वादर पोर्ट (चीन का बंदरगाह) से सिर्फ 112 किमी दूर है। यह बंदरगाह अमेरिका को पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों जैसे तांबा और एंटीमनी तक आसान पहुंच देगा।



अकरम ने कहा ऐसे सीक्रेट सौदे से देश के हालात खराब हो सकते हैं। ढक्कड़ ने मांग की कि सरकार अमेरिका के साथ हुए सौदों का पूरा ब्योरा जनता को बताए। ढक्कड़ के नेता ने



राजौरी में मुठभेड़ के बाद गायब हुए 4 आतंकीयों को तलाशने में जुटा सुरक्षा बल

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकीयों से मुठभेड़ हुई इसके बाद वे अंधेर का फायदा उठाकर फरार हो गए। मंगलवार की रात दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई थी। इसके बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। बीरथुब में हुए इस एनकाउंटर के बाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ की जॉइंट टीम यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। मंगलवार की पूरी रात चली सर्चिंग के बाद बुधवार सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां 4 आतंकीयों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षाबल राजौरी-कोटरणका-बुधाले सड़क से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं। वहीं, आतंकीयों से टेरर फ्लिग केस को लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईई) श्रीनगर, गान्दरबल, वडगाम, अन्तनगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बादीपुरा और गान्दरबल में छापेमारी कर रही है।

कुलगाम में 2 हुए थे डेर इससे पहले पिछले माह सितंबर में सेना ने कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकीयों को मार गिराया था। गुड्डर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सेना ने इन आतंकीयों को मार दिया था। इस दौरान घायल हुए दो जवान भी शहीद हुए थे। मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमीर अहमद डार के तौर पर हुई थी। वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में यह भी शामिल था।

सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में चचेरा भाई डीएसपी संदीपन अरेस्ट

गुवाहाटी (एजेंसी)। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया गया है। संदीपन, सिंगर के चचेरे भाई हैं। हादसे के वक्त वे सिंगापुर में साथ थे। अधिकारी ने बताया कि संदीपन से जुबीन की मौत को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षडयंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया है। बात दें कि जुबीन की मौत के मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेरिटवेल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके दो बहू सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को अरेस्ट किया गया था। जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ था। सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेरिटवेल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्होंने वाटर एडवेंचर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। दावा किया गया कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई थी।

आंध्र प्रदेश में पटाखा फेक्ट्री में विस्फोट... 6 लोगों की मौत, कई बुरी तरह झुलसे

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के डोंडीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के रावधरम में एक पटाखा फेक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बुरी तरह झुलस गए शवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। कई लोग घायल हैं। प्रशासन के अनुसार मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। पुलिस अधिकारी राहुल मीणा ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों के शव बुरी तरह झुलसे हैं। मृतक पटाखा फेक्ट्री के मजदूर हो सकते हैं। शवों की पहचान का जा रही है। पटाखा फेक्ट्री के पास मेयुफेक्ट्री का लाइसेंस था। लोकल रिपोर्ट्स में पटाखा बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका की खबरें हैं। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में पूरी फेक्ट्री आग की लपटों से घिरी दिखी। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति का शव पूरी तरह झुलसा दिख रहा है। वहीं घटना पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम नायडू ने पोस्ट कर लिखा कि इस दुर्घटना में कई लोगों की जान जाने की खबर से गहारा दुःख हुआ है। मैंने अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों, तर्मान स्थिति, राहत कार्यों और चिकित्सा सहायता के बारे में बात की है।

राजस्थान में कई दवाओं के सैपल जांच में फेल... लेकिन रिपोर्ट आने तक बिक गईं हजारों दवाएं

जयपुर (एजेंसी)। कफ सिरप से बच्चों के मौत का मामला अभी सुर्खियों में है। लेकिन इसी बीच लोगों की सेहत से जुड़ी एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिर्फ राजस्थान में एक साल के अंदर कई बड़ी बीमारियों की दवाओं के सैपल फेल हुए हैं। लेकिन उससे पहले ही दवाओं की हजारों गोलियां बेची जा चुकी हैं। जिन दवाओं के सैपल फेल हैं, उन्हीं एंटी बायोटिक से लेकर कॉर्डिक अरेस्ट जैसे गंभीर बीमारियों की टैबलेट शामिल हैं। वहीं, सैपल में कई दवाओं से साल्ट भी गायब मिले। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दवा नियंत्रण कानून में कई खामियां हैं। इसका फायदा उठाकर आम लोगों के जीवन से खेलेने का कारोबार बेधड़क जारी है। दवाइयों के सैपल फेल होने का मामला राजस्थान के औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में सामने आया। औषधि नियंत्रण विभाग ने लापरवाही सामने आई की लेबोरेटरी में जांच हो रही है और नतीजे भी आ रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग के अनुसार सैकड़ों दवाओं के सैपल फेल हुए हैं। जांच में इमोबिलिजेशन, वलेंट्यूनिंग एरिड टैबलेट, सिफ्राप्लोक्ससिन, सेफप्राडॉक्सिन, सेफटाइड्रोन इंजेक्शन के 6 बैच फेल मिले। जांच से पहले मैडिसेर लिमिटेड की 1 लाख से अधिक दवाइयां बिक चुकी थीं।

स्टेराइड- बीटामेथॉसॉन के 3 बैच फेल मिले। रिपोर्ट आई तब तक मेडिडेल बायोटेक की 30 हजार दवा बिक चुकी थी।

लिवोसिट्रोनिन, मोटेल्कास्ट के 4 बैच सैपल में फेल निकले। लेकिन रिपोर्ट आने तक थेरापिन फार्मास्यूटिकल की 35 हजार दवाएं बिक चुकी थीं।

बिहार में सख्ती से लागू करें आचार संहिता, घोषणाएं और नीतिगत फैसले पर लगा बैन

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से पोस्टर, बैनर हटाने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया है। 6 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम को घोषणा के साथ आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आचार संहिता के सख्त कार्यान्वयन के निर्देश दिए। यह संहिता न केवल राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, खासकर बिहार से संबंधित नीतिगत फैसलों और घोषणाओं के मामले में।



पर बिना मालिक की सहमति के झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर रोक है। निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन या धरना देने की भी मनाही है। शिकायतों के निपटारे के लिए आयोग ने 24 घंटे चलने वाली शिकायत निगरानी प्रणाली शुरू की है। शिकायतों के निपटारे के लिए आयोग ने 24

घंटे चलने वाली शिकायत निगरानी प्रणाली शुरू की है। नागरिक कॅल सेंटर नंबर 1950 या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सी-विजिल ऐप के जरिए एमसीसी उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है, जिस पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करने के लिए राज्य में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। आयोग ने मंत्रियों को आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार से अलग रखने और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न करने का निर्देश दिया है। चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी है। सभी अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने, सभी दलों के साथ समान व्यवहार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। सार्वजनिक स्थानों, जैसे मैदान और हेलीपैड, का आवंटन पहले आ-पहले पाओ के आधार पर निष्पक्ष रूप से करने के लिए सुविधा मॉड्यूल को सक्रिय कर दिया है।

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री पर साधा निशाना और बोलीं- एक्टिंग पीएम की तरह काम कर रहे शाह, बन जाएंगे एक दिन मीर जाफर



कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे देश के 'एक्टिंग प्रधानमंत्री' हों, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। दरअसल सीएम ममता बनर्जी मीडिया से बातचीत कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने कहा, कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन हर काम ऐसे करते हैं जैसे वही प्रधानमंत्री हों। प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हैं, पर कुछ नहीं बोलते। मेरा पीएम से अनुरोध है कि उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि एक दिन वही मीर जाफर की तरह आपक खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ममता ने आगे कहते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता बंगाल में मतदाता सूची से एक लाख नाम हटाने की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र पर हमला है।

शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर 12 नवंबर को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

उद्धव ठाकरे ने भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका चुनाव चिन्ह 'धनुष-बाण' आवंटित किया था। उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 में होना है, इसलिए इस मामले पर

तत्काल विचार करने की जरूरत है, जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले को सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि हम 12 नवंबर को सभी पक्षों की सुनवाई करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो हम 13 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखेंगे। कपिल सिब्बल ने शिवसेना (यूबीटी) गुट की तरफ से दायर एक अन्य याचिका पर भी तत्काल सुनवाई की मांग की। इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उमर फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के

16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि कपिल सिब्बल को संयुक्त सुनवाई के लिए भारत के सीजेआई की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरी याचिका एक अलग बेंच के सामने लिंबित है। बुधवार की सुनवाई से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेजीवार ने कहा कि यह फैसले पर निर्भर करता है कि इस देश को किस ओर लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि यहां लोकतंत्र विना रहना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। हम यही अपेक्षा करते हैं कि न्यायालय का फैसला न्यायसंगत होगा और संविधान पर

आधारित होगा। वडेजीवार ने कहा कि यह जनता को यह दिखाने का सुनहरा अवसर है कि देश संविधान और कानून के शासन से चलता है।

10वीं फेल मिस्टर खड़गे, फिर भी भारत के कर्ज पर दे रहे हैं लेफ्टर?

बीजेपी नेता ने कर्नाटक सरकार में मंत्री की शिक्षा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं। विष्णु वर्धन ने एफएस पर एक पोस्ट कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को दसवीं फेल बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं फेल मिस्टर खड़गे, लेकिन फिर

भी भारत के कर्ज पर लेफ्टर दे रहे हैं? दरअसल प्रियांक खड़गे ने एफएस पर एक पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार के 'अमृतकाल' में भारत का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। देश का कुल कर्ज अब 181 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह पिछले सात सालों में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ है। वर्धन ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का बाहरी कर्ज भी 10.1 फीसदी बढ़कर 736.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

यह सात सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया था कि इसी अवधि में भारतीय बैंकों ने ज़ीते एक दशक में 12.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। प्रियांक ने इसी पोस्ट में यह भी कहा कि इसके बावजूद पीएम मोदी ने बिहार में वोट खरीदने के लिए करदाताओं के 7,500 करोड़ रुपए की राशि बांटी। आर्थिक मांचे पर देश कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार का प्रचार तंत्र करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर

खर्च कर जनता को यह भरोसा दिलाने में जुटा है कि 'सब चंगा है'। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियांक खड़गे की इस पोस्ट पर बीजेपी नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने उन पर प्रहार करते हुए कहा कि 10वीं फेल मिस्टर खड़गे अब भारत के कर्ज पर ज्ञान दे रहे हैं? आपको ही मंत्रालय पर 5,588.33 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जबकि कर्नाटक के सरकारी विभागों पर कुल 10,342.13 करोड़ का बकाया है।

सीजेआई पर जूता उछालने के बाद सीनाजोरी, बोला- फिर ऐसा ही करुंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अबीर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर अब चोरी ऊपर से सीनाजोरी पर उतर आए हैं। उन्हें उनकी हरकत के लिए माफ कर दिया गया है लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किशोर ने कहा कि भगवान का आदेश हुआ तो फिर कुछ इसी तरह करुंगा। उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा था, इसलिए किया। मैंने परमात्मा का काम किया। यह मेरा दिव्य कर्तव्य था। उन्होंने कहा कि उन्हें अर्पण किए पर कोई पछतावा नहीं है और अगर परमात्मा फिर आदेश देंगे तो वे दोबारा ऐसा करेंगे।



लेकर पहुंचे थे। उन्होंने नारे लगाए, 'सीजेआई का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। इस घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जूता फेंकने का नहीं है बल्कि संविधान पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तलाइन प्लेटफॉर्म पर सीजेआई के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां और धमकियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकार को हटाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पुलिस इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, चाहे द्विवेदी से कहा कि आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जूता फेंकने का नहीं है बल्कि संविधान पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तलाइन प्लेटफॉर्म पर सीजेआई के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां और धमकियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकार को हटाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पुलिस इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, चाहे द्विवेदी से कहा कि आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जूता फेंकने का नहीं है बल्कि संविधान पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तलाइन प्लेटफॉर्म पर सीजेआई के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां और धमकियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकार को हटाना चाहिए।

निर्वाचित करने के लिए बैरिकेड लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, राकेश किशोर के पड़ोसियों ने बताया कि उनके खिलाफ पहले भी हिंसक व्यवहार की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। 70 वर्षीय पुरुषोत्तम ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हंगामा किया। 2021 में भी उन्होंने एक नजुम के साथ हाथापाई की थी।



हुए हैं। एक अन्य जानकारी अनुसार हिमाचल प्रदेश में तीसरे दिन भी स्नोफॉल जारी है। लाहौल-स्पीति में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, विलासपुर जिले में एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई है।

में रोजाना पांच हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

नदियां उफान पर बाढ़ के हालात

दूसरी ओर, बिहार में लोटते मानसून और नेपाल में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुपौल में 5 हजार से अधिक घरों में पानी भर गया, जबकि मधुबनी जिले में करीब एक लाख लोग प्रभावित हैं। इस बीच, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने आगले 48 घंटों तक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं का विवरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में एसआईआर के तहत 3.66 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जूता फेंकने का नहीं है बल्कि संविधान पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तलाइन प्लेटफॉर्म पर सीजेआई के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां और धमकियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकार को हटाना चाहिए।

श्रीष अदालत ने कहा कि सभी के पास मतदाता सूची का मसौदा है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग का पक्ष रखने के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि आदमी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जूता फेंकने का नहीं है बल्कि संविधान पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्तलाइन प्लेटफॉर्म पर सीजेआई के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां और धमकियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें सरकार को हटाना चाहिए।

धर्म से बचने के लिए अतिरिक्त मतदाताओं की पहचान का खुलासा किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने कहा कि आप हमसे सहमत होंगे कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि आपके द्वारा प्रकाशित मसौदा सूची में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे और हमने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जो स्थानांतरित हो गया है वह ठीक है, लेकिन यदि आप किसी को हटा रहे हैं तो कृपया नियम 21 और एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) का पालन करें। उन्होंने कहा, हमने यह भी कहा कि जिनके भी नाम

हटाए गए हैं, कृपया उनके आंकड़े अपने निर्वाचन कार्यालयों में जमा कराएं। अब अंतिम सूची आंकड़ों में वृद्धि प्रतीत होती है और सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति है - जोड़े गए नामों की पहचान क्या है, क्या वे हटाए गए नाम हैं या नए नाम हैं। द्विवेदी ने जवाब दिया कि अधिकतर नाम नए मतदाताओं के हैं और कुछ पुराने मतदाता भी हैं, जिनके नाम मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ऐसे किसी मतदाता ने शिकायत या अपील नहीं की है जिसका नाम हटाया गया है।

